7

दी नेक्स्ट पोस्ट

साप्ताहिक

3 प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का यहां ले सकेंगे लुत्फ, जल्द हो जाएगा तैयार

5 जौनपुर में नितिन गडकरी

8 धर्मशाला में अश्विन रचेंगे इतिहास

UPHIN51019 | वर्षः 01, अंकः 32 | पृष्ठ संख्याः 8 | मूल्यः 1.00 रू. | सोमवार 04 मार्च, 2024

नए भारत के निर्माण के लिए हम देशभर के कारखानों के पुनरोद्धार में निरंतर जुटे हुए हैं। झारखंड के सिंदरी का खाद कारखाना इसका एक बड़ा उदाहरण है।

योगी कैबिनेट का विस्तार जल्द

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मुलाकात की।

– लखनऊ,संवाददाता

दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मुलाकात की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले एक दो दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में सहयोगी दलों में सीट शेयरिंग तय होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे हैं।

भाजपा यूपी में सहयोगी दलों ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा (एक सीट), अपना दल (दो सीट), निषाद पार्टी (एक सीट) और रालोद (दो सीट) को छह सीटें देने पर सहमत हो गई है। संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में ओमप्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं, एनडीए में शामिल आरएलडी से भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले शुक्रवार या शनिवार को सौ से अधिक उम्मीदवारों की सूची और 10 मार्च तक करीब 250 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे।

केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पूर्व प्रधानमंत्री निवास पर पार्टी के शीर्ष नेताओं की करीब छह घंटे तक चली बैठक में 21 राज्यों की 300 सीटों पर उम्मीदवारो का पैनल तैयार कर लिया गया है। इस बैठक में पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गठबंधन पर बातचीत तय होने तक उम्मीदवार घोषित नहीं करने का फैसला किया गया है।

RLD के एक विधायक का मंत्री बनना लगभग तय

यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सका है। वहीं, यूपी मंत्रिमंडल में रालोद के एक विधायक को जगह मिल सकती है। माना जा रहा है कि रालोद के एक विधायक का मंत्री बनना लगभग तय है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जहां दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक हुई तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मुलाकात की। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है।

वहीं, मंत्रिमंडल में रालोद के एक विधायक को शामिल किया जा सकता है। वैसे भी हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में रालोद के सभी विधायकों ने भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में वोट किया था।

माना जा रहा है कि यूपी मंत्रिमंडल विस्तार में आरएलडी के एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह मुस्लिम और गुर्जर चेहरे पर दांव खेलने की तैयारी में हैं।

बताया गया कि आज यानी शुक्रवार को जेपी नड्डा और जयंत चौधरी की मुलाकात होगी। आज रालोद के साथ भाजपा का औपचारिक गठबंधन हो सकता है। सूत्र के अनुसार, भाजपा ने रालोद को बागपत, बिजनौर सीट दी है। यूपी में मंत्रिपरिषद विस्तार में रालोद के दो विधायक मंत्री बन सकते हैं। रालोद का एक कैबिनेट और एक राज्यमंत्री पद तय माना जा रहा है। सूत्र की मानें तो राजभर की पार्टी से सिर्फ राजभर मंत्री बनेंगे।

भाजपा यूपी में सहयोगी दलों ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा (एक सीट), अपना दल (दो सीट), निषाद पार्टी (एक सीट) और रालोद (दो सीट) को छह सीटें देने पर सहमत हो गई है। संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में ओमप्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जा सकता है।

कुत्ते की तरह भौंकने लगा सात साल का मासूम

बैठने से खाने तक बदला अंदाज फिर हुई ऐसी मौत...कांप गए घरवाले

आगरा। सात साल के मासूम बच्चे की मौत जिस तरह हुई उसे देखकर हर कोई हैरान है। मरने से पहले उसका अंदाज पूरी तरह बदल गया था। उसे पानी से डर लग रहा था, तो कभी कुत्ते की तरह भौंकने लगता। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के थाना खेरागढ़ क्षेत्र में सात साल के मासूम की दर्दनाक मौत हुई। बच्चे को तीन महीने पहले कुत्ते ने काट लिया था। परिवार के मुताबिक बच्चे का इलाज भी कराया गया। लेकिन अब जाकर उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया। मासूम को पानी से डर लगने लगा। वहीं कभी–कभी उसके मुंह से कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज भी आती थी। इससे घबराए परिवार के लोग मासूम को डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, तब जानकारी हो सकी कि ये सब रेबीज के कारण हो रहा है।

पानी से लगने लगा था डर

थाना खैरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हाथवंत निवासी मुन्नेश कुमार के सात वर्षीय बेटे सचिन की हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसे पानी से डर लगने लगा। ये देख परिवार के लोग घबरा गए। उसे तत्काल ही अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि मासूम को रेबीज का इन्फेक्शन फैल गया है। बेटे की हालत देख पिता चीखने चिल्लाने लगा। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई, जिससे घर में कोहराम मच गया।

तीन माह पूर्व काटा था कुत्ते ने परिवार के लोगों ने बताया कि सचिन दयाराम बघेल विद्यालय हाथवंत में पढ़ने जाता था। तीन माह पूर्व घर के समीप खेलते समय आवारा कुत्ते ने काट लिया था। परिजनों द्वारा उसको कुत्ता काटने की दवा खिला दी थी। 29 फरवरी की रात को सचिन पर कुत्ता काटे का असर आ गया। परिजन उसे उपचार के लिए फिरोजाबाद ले जा रहे थे, तभी उसकी मौत हो गई। सचिन की मौत होने की जानकारी होने पर देखने वालों की भीड़ लग गई।

गांव वालों में भी है दहशत

बताया गया है कि जिस कुत्ते ने सचिन को काटा था, वो गांव के कई और लोगों को भी काट चुका है। ऐसे में सचिन की मौत के बाद उन लोगों में भी दहशत है।

संदेशखाली से कन्हैयालाल हत्याकांड जैसा असर होने की उम्मीद, प्रधानमंत्री उठा सकते हैं ये मुद्दा

दिल्ली। चुनावी यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं संदेशखाली मुद्दे को उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही राजस्थान विधानसभा चुनावों के दौरान कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला जोरशोर से उठाया था, जिससे पूरे राजनीतिक समीकरण पलट गए थे। माना जा रहा है कि भाजपा वही रणनीति पश्चिम बंगाल में भी अपना सकती है भाजपा का अनुमान है कि संदेशखाली मुद्दे का पश्चिम बंगाल में कन्हैयाल हत्याकांड जैसा असर हो सकता है। कन्हैयालाल हत्याकांड के कारण राजस्थान में मतदाताओं का पूरी तरह ध्रुवीकरण हो गया था और बेहतर कामकाज के बाद भी अशोक गहलोत को करारी हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा का अनुमान है कि इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी संदेशखाली कांड ममता बनर्जी सरकार पर भारी पड़ सकता है। 55 दिनों तक शाहजहां शेख पर कोई कार्रवाई न होने के कारण लोग ममता बनर्जी सरकार से खासे नाराज हैं और इसे एक वर्ग विशेष के तुष्टिकरण से जोड़कर देख रहे हैं।

भाजपा सूत्रों का कहना है कि लोग संदेशखाली घटनाओं को 1980 के दशक में घटी कश्मीर की घटनाओं से जोड़कर भी देख रहे हैं, जहां हिंदू महिलाओं से इसी तरह की अशोभनीय घटनाएं घटी थीं। भाजपा का मानना है कि लोगों की यह नाराजगी लोकसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है।

इस मुद्दे पर लोगों के आक्रोश को देखते हुए भाजपा इस पर पूरी तरह आक्रामक हो गई है। उसके कई नेता लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। भाजपा के कई केंद्रीय मंत्री और संगठन के बड़े पदाधिकारी जल्द ही संदेशखाली की यात्रा कर इस मामले को और तेजी देने का काम कर सकते हैं। भाजपा इस मामले को दिल्ली–बंगाल सहित पूरे देश में उठाने की रणनीति बना रही है। माना जा रहा है कि चुनावी यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस मुद्दे को उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही राजस्थान विधानसभा चुनावों के दौरान कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला जोरशोर से उठाया था, जिससे पूरे राजनीतिक समीकरण पलट गए थे। माना जा रहा है कि भाजपा वही रणनीति पश्चिम बंगाल में भी अपना सकती है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति पर पकड़ रखने वाले पत्रकार सांतनु मुखर्जी के अनुसार, संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख द्वारा हिंदू समुदाय की महिलाओं के साथ हुए अत्याचार की बात पूरे पश्चिम बंगाल में फैलती जा रही है। अब संदेशखाली की तरह राज्य में कुछ अन्य मामले भी सामने आ रहे हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने लोगों की जमीन हड़प ली हैं और उन्हें स्थानीय प्रशासन से प्रताड़ित किया जा रहा था।

कुछ स्थानों से हिंदू समुदाय के श्रमिकों के पलायन करने की खबरों ने भी राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। यही कारण है कि इस मुद्दे का राजनीतिक असर होने की आशंका से राज्य सरकार को अपनी गलती का आभास हो गया है। शाहजहां शेख के मामले पर ममता बनर्जी के बदले सुर भी यह बताते हैं कि उन्हें भी इस मामले में अपनी गलती का एहसास हो गया है।

राज्य में मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 30 फीसदी है। यह आबादी कई लोकसभा क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों को अकेले दम पर प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि वामपंथी दलों का शासन रहा हो, या तृणमूल कांग्रेस का, किसी के लिए भी मुस्लिमों की उपेक्षा करना संभव नहीं रह गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को लगभग 40 फीसदी हिंदू मतदाताओं का वोट मिला था। यदि इस चुनाव में यह आंकड़ा थोड़ा भी बढ़ जाता है, तो चुनाव परिणाम पूरी तरह बदल सकते हैं। वहीं, मुस्लिम समुदाय का वोट विधानसभा चुनाव में पूरी तरह ममता बनर्जी के साथ एकजुट हो गया था। यदि एक बार फिर ऐसा होता है तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस और वामदलों को हो सकता है।

सम्पादकीय

भारत में गरीबी के 5 प्रतिशत से नीचे चले जाने का दावा गलत

कल्याणकारी योजनाओं के तहत आपूत की गई मुफ्त राशि के आधार पर गरीबी के स्तर को नकारना महज कुतर्क होगा

कल्याणकारी योजनाओं के तहत आपूर्ति की गई मुफ्त राशि के आधार पर गरीबी के स्तर को नकारना महज कुतर्क होगा, क्योंकि यह सिर्फ गरीबी को थोड़ा सहनीय बनाता है, लेकिन कमाई के स्तर को बढ़ाकर गरीबी को खत्म नहीं करता है। यह सिर्फ मुफ्तखोरी और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उपभोग स्तर को बढ़ाने की राजनीति है, केवल यह दावा करने के लिए कि गरीबी कम हो गई है, जो वास्तव में बेकारी और कम कमाई के स्तर के कारण बदतर होती जा रही है। नेशन सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) द्वारा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएसः 2022–23) के प्रकाशन के ठीक बाद, पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 की पूर्व संध्या पर गरीबी पर राजनीति शुरू कर दी गई है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वी. आर सुब्रमण्यम ने दावा किया है कि देश में गरीबी 5 प्रतिशत से नीचे आ गई है, खुदरा मुद्रास्फीति को बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया गया है, तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कमजोर होने और भारत का 'कुछ लोगों तक ही सीमित' होने की बात गलत है।

जो लोग एचसीईएस के विवरण के बारे में नहीं जानते, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि बीवीआर सुब्रमण्यम आखिर कह क्या रहे हैं। वह कह रहे हैं कि गरीब लोग वे हैं जो प्रति दिन 32 रुपये से कम कमाते हैं, और ऐसे लोगों का प्रतिशत 5 से भी कम होने की उम्मीद है। गरीबी रेखा के इस बेतुकी स्तर आलोचना पहले ही 2011–12 में हो चुकी है, और उस समय अधिकांश लोगों ने इसे खारिज कर दिया था, जब तत्कालीन योजना आयोग 32 रुपये प्रति दिन की कमाई पर गरीबी रेखा का विचार लेकर आया था। अब एक दशक बाद एक शीर्ष सरकारी अधिकारी का 32 रुपये की गरीबी रेखा पर आधारित तर्क दोगुना बेतुका है। यह तर्क देने के लिए उन्होंने हाल के 2022–23 सर्वेक्षण को आधार बनाया। इस दावे का उद्देश्य आगामी लोक सभा आम चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद करना है, जब वह और भाजपा अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रयास कर रहे होंगे, और वे मोदी राज में वृद्धि और विकास की कथा को आगे बढ़ा रहे होंगे। अधिकारी ने आगे कहा, 'अगर हम प्रतिदिन 32 रुपये पर जायें, जो कि 2011–12 की अंतिम स्वीकृत गरीबी रेखा थी, और तब से मुद्रास्फीति के रुझान को ध्यान में रखते हुए उस स्तर को दोगुना कर लगभग 60 रुपये प्रतिदिन कर दिया जाए, तो आप देखेंगे गरीबी 10 प्रतिशत से कम है।' इसका मतलब है कि शीर्ष अधिकारी अपने पहले के दावे का खंडन करते हैं कि गरीबी रेखा 5 प्रतिशत से नीचे चली गई है, जो 2011–12 की कीमतों पर थी, लेकिन मौजूदा कीमतों पर यह 10 प्रतिशत से नीचे होगी।

अब आइए एचसीईएस के अनुसार 2022–23 में विभिन्न वर्गों में मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) औसत पर आते हैं। श्री सुब्रमण्यम ने स्वयं नोट किया कि निचले 5 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के लिए औसत उपभोग स्तर 1373 रुपये था, जबकि अगले 5 प्रतिशत के लिए यह 1782 रुपये था। कोई कल्पना ही कर सकता है कि यदि कोई व्यक्ति 1373 रुपये या 1782 रुपये प्रति माह पर भी जीवनयापन करता है तो वह गरीब कैसे नहीं है।

हाल ही में नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक ने 11 फीसदी लोगों को गरीबी रेखा के नीचे रखा था, पीएम मोदी ने दावा किया था कि उनके शासन में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पीएमजीकेएवाई के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है, जबकि सरकार को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अनुमानित 81.4 करोड़ गरीबों में से 1.4 करोड़ गरीबों की पहचान करना बाकी है। इसमें प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले गरीबों की संख्या एक पहेली बनी हुई है।

अब हम एचसीईएस 2022–23 परिणाम पर आते हैं। सर्वेक्षण पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। एचसीईएस 2011–12 में 347 आइटम थे, जबकि 2022–23 में कई नए आइटम जोड़े और कई हटा दिए गये। वर्तमान सर्वेक्षण में कुल मिलाकर 405 आइटम थे। एक प्रश्नावली के स्थान पर तीन प्रश्नावली का प्रयोग किया गया – 1. खाद्य पदार्थों पर 2. उपभोग्य सामग्रियों एवं सेवाओं की वस्तुओं पर, और 3. टिकाऊ वस्तुओं पर। इसके अतिरिक्त, घरेलू विशेषताओं के साथ–साथ घरों के सदस्यों के जनसांख्यिकीय विवरण पर जानकारी एकत्र करने के लिए एक और प्रश्नावली थी। डेटा संग्रह का तरीका पेन–एंड–पेपर पर्सनल इंटरव्यू (पीएपीआई) से बदलकर कंप्यूटर–असिस्टेडपर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) कर दिया गया। सर्वेक्षण स्वयं चेतावनी देता है कि पिछले सर्वेक्षणों के साथ एचसीईएस 2022–23 के परिणामों की तुलना करते समय इन परिवर्तनों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। एमपीसीई के अनुमान, जिसके आधार पर श्री सुब्रमण्यम ने तर्क दिया है, में विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से परिवारों द्वारा मुफ्त में प्राप्त और उपभोग की जाने वाली कई वस्तुओं की खपत की मात्रा पर जानकारी एकत्र करने के लिए एक अलग अतिरिक्त प्रावधान भी है। नतीजतन, मुफ्त खाद्य पदार्थों और मुफ्त गैर–खाद्य वस्तुओं जैसे लैपटॉप, पीसी, टैबलेट, मोबाइल हैंडसेट, साइकिल, कपड़े, जूते (स्कूल जूते) आदि के मूल्य आंकड़े 'उचित विधि' का उपयोग करके जोड़ दिये गये हैं।

इसलिए यह स्पष्ट है कि एचसीईएस 2022–23 डेटा पहले के डेटा से अलग है जिसे स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है अन्यथा यह हमें लोगों की वास्तविक कमाई और उनकी गरीबी के बारे में गलत निष्कर्ष पर पहुंचा देगा।

2022–23 में औसत अनुमानित एमपीसीई ग्रामीण भारत में 3,773 रुपए शहरी भारत में 6,459 रुपये है। ग्रामीण लोग भोजन पर 46 प्रतिशत और गैर–खाद्य पर 54 प्रतिशत खर्च करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह क्रमशः 39 प्रतिशत और 61 प्रतिशत है। एमपीसीई द्वारा रैंक किये गये भारत की ग्रामीण आबादी के निचले 5 प्रतिशत का औसत एमपीसीई 1,373 रुपयेहै, जबकि यह शहरी क्षेत्रों में समान श्रेणी की जनसंख्या के लिए 2,001 रुपये। एमपीसीई द्वारा रैंक किए गए भारत की ग्रामीण और शहरी आबादी के शीर्ष 5 प्रतिशत का औसत एमपीसीई क्रमशः 10,501 रुपए और 20,824 रुपये है। यह अंतर बहुत गहरा है जो मोदी शासन में असमानता को दर्शाता है। 2022–23 के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की खपत का स्तर 3773 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 6459 रुपये है। यह स्तर दर्शाता है कि औसत लोग अपनी कम कमाई के कारण बड़ी कठिनाई में हैं

2022–23 में औसत एमपीसीई में ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज की हिस्सेदारी 4.91 प्रतिशत और खाद्य पदार्थों की 46.38 प्रतिशत थी। शहरी क्षेत्रों में ये क्रमशः 3.64 और 39.17 प्रतिशत हैं।

यह जानकर निराशा हो सकती है कि लगभग 50प्रतिशत ग्रामीण आबादी का औसत एमपीसीई 3,094 रुपये से कम है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 4,963 रुपये है। ग्रामीण क्षेत्रों में शीर्ष तीन फ्रैक्टाइल 80–90 प्रतिशत, 90–95 प्रतिशत और 95–100 प्रतिशत का औसत एमपीसीई क्रमशः 5356 रुपये, 6638 रुपये और 10,501 रुपये था, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 9,582 रुपये, 12,399 रुपये और 20,824 रुपये था। सबसे कम उपभोग व्यय में फिर से असमानता देखी गई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 0–5 प्रतिशत सबसे कम फ्रैक्टाइल में 1373 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 95–100 प्रतिशत उच्चतम फ्रैक्टाइल में 20,824 रुपये प्रति माह है। ऐसी असमानता स्वीकार्य नहीं है, भले ही हम ग्रामीण और शहरी उच्चतम और निम्नतम फ्रैक्टाइल की अलग–अलग तुलना करें।

अनुसूचित जनजाति (एसटी) का औसत एमपीसीई ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम 3,016 रुपये है, जबकि एससी के लिए यह 3,474 रुपये, ओबीसी के लिए 3,848 रुपये और अन्य के लिए 4,392 रुपये है। शहरी क्षेत्रों में सबसे कम एमपीसीईएससी के लिए 5,307 रुपये है, जबकि एसटी के लिए 5,414 रुपये, ओबीसी के लिए 6,177 रुपये और अन्य के लिए 7,333 रुपये है।

एमपीसीई के अनुमान के अनुसार, 2022–23 में मुफ्त वस्तुओं के अनुमानित मूल्यों के साथ औसत अनुमानित एमपीसीई3,860रुपए ग्रामीण भारत में और शहरी भारत में 6,521 रुपये था। एमपीसीई द्वारा रैंक किए गये भारत की ग्रामीण आबादी के निचले 5 प्रतिशत का औसत एमपीसीई1,441 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 2,087 रुपये था। एमपीसीई द्वारा रैंक किए गए भारत की ग्रामीण और शहरी आबादी के शीर्ष 5 प्रतिशत का औसत एमपीसीई क्रमशः 10,581 और 20,846 रुपये था। कल्याणकारी योजनाओं के तहत आपूर्ति की गई मुफ्त राशि के आधार पर गरीबी के स्तर को नकारना महज कुतर्क होगा, क्योंकि यह सिर्फ गरीबी को थोड़ा सहनीय बनाता है, लेकिन कमाई के स्तर को बढ़ाकर गरीबी को खत्म नहीं करता है। यह सिर्फ मुफ्तखोरी और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उपभोग स्तर को बढ़ाने की राजनीति है, केवल यह दावा करने के लिए कि गरीबी कम हो गई है, जो वास्तव में बेकारी और कम कमाई के स्तर के कारण बदतर होती जा रही है। बढ़ती कीमतों ने पहले से ही जीवनयापन की लागत का संकट पैदा कर दिया है।

फिनटेक क्रांति में बाधा बनती केंद्र सरकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में फिनटेक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में सुझाव दिया कि रिजर्व बैंक फिनटेक कंपनियों और स्टार्टअप की चिंताओं को दूर करने के लिए उनके साथ मासिक बैठक करे।

'वित्त' का काम जोखिम और समय से बेहतर तरीके से निपटने के लिए वास्तविक अर्थव्यवस्था की मदद करना है। भारत में वित्त सही रहे,इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि भौगोलिक और वर्ग की विविधता के साथ रहने वाले लोगों के जीवन को सही बनाने के लिए उत्पादों और प्रक्रियाओं पर जोखिम उठाया जाए और नवाचार किया जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में फिनटेक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में सुझाव दिया कि रिजर्व बैंक फिनटेक कंपनियों और स्टार्टअप की चिंताओं को दूर करने के लिए उनके साथ मासिक बैठक करे। फिनटेक कंपनियां ऐसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जहां नियमन स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। भारत में मौजूदा वित्तीय प्रणाली के कमजोरी को देखते हुए फिनटेक महत्वपूर्ण हो सकते हैं,परंतु केंद्र सरकार की एकाधिकारी प्रवृत्ति से फिनटेक को काफी नुकसान हो रहा है।

इस संपूर्ण मामले को समझने के लिए आवश्यक है कि यह जानें कि आखिर 'फिनटेक' किसे कहते हैं? फिनटेक 'फाइनेंशियल टेक्नालॉजी' का संक्षिप्त रू‍प है। वित्तीय कार्यों में प्रोद्योगिकी के उपयोग को फिनटेक कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह पारंपरिक वित्तीय सेवाओं और विभिन्न कंपनियों तथा व्यापार में वित्तीय पहलुओं के प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन है। फिनटेक शब्द का प्रयोग उन नई तकनीकों के संदर्भ में किया जाता है,जिनके माध्यम से वित्तीय सेवाओं में सुधार और स्वायत्तता लाने का प्रयास किया जाता है। डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ऋ ण,बैंक टेक, इंश्योर टेक, क्रिप्टोकरेंसी आदि फिनटेक के कुछ प्रमुख घटक हैं। हालांकि वर्तमान में फिनटेक के तहत कई अलग–अलग क्षेत्र और उद्योग जैसे –शिक्षा, खुदरा बैंकिंग, निधि जुटाना और गैर लाभकारी कार्य, निवेश प्रबंधन आदि भी शामिल किये जाते हैं।

'वित्त' का काम जोखिम और समय से बेहतर तरीके से निपटने के लिए वास्तविक अर्थव्यवस्था की मदद करना है। भारत में वित्त सही रहे,इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि भौगोलिक और वर्ग की विविधता के साथ रहने वाले लोगों के जीवन को सही बनाने के लिए उत्पादों और प्रक्रियाओं पर जोखिम उठाया जाए और नवाचार किया जाए। यह उस वित्तीय आर्थिक नीति को खारिज करता है, जहां सरकार और उसकी एजेंसियां उत्पादों और प्रक्रियाओं पर विस्तृत नियंत्रण के साथ एक केंद्रीय नियोजन प्रणाली चलाती हैं।

फिनटेक क्षेत्र में नियामकों को एक बारीक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है और कोशिश होनी चाहिए कि बिना वित्तीय स्थिरता के लक्ष्य से समझौता किए नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। करीब 140 करोड़ की आबादी वाले देश में फिनटेक क्रांति वित्तीय समावेशन का महत्वपूर्ण अंग बन सकती है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि इस क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहन मिले। नवाचार के माध्यम से ही अत्यंत विविधता वाले अपने देश में वित्तीय प्रणाली को टेक्नालॉजी से जोड़कर आम जन तक पहुंचाया जा सकता है। मौजूदा वित्तीय प्रणाली इसकी विविधता के साथ कदमताल नहीं कर पा रही है। वित्तीय आर्थिक नीति एक केंद्रीय नियोजन प्रणाली के रूप में तैयार की जाती है। उत्पादों, प्रक्रियाओं और सरकार नियंत्रित एकाधिकार ऊपर से थोपा जाता है। इसके बाद विशिष्ट भारतीय शैली के केवाईसी और मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों से भी फिनटेक क्षेत्र में नवाचार की गुंजाइश घटती जा रही है। यह सही है कि नियामक भी फिनटेक कारोबार तथा उनसे उत्पन्न होने वाले खतरों को समझने की प्रक्रिया में हैं।

हालांकि नियामक अभी फिनटेक अंशधारकों के साथ नियमित संवाद करता है, लेकिन एक औपचारिक व्यवस्था बन जाने से दोनों पक्षों को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने वित्तीय सेवा विभाग से कहा है कि वे फिनटेक और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एक दिन की कार्यशाला का आयोजन करे,जहां वे अपनी चिंताएं सामने रख सकती हैं। परंतु सरकार के ये प्रयत्न मूलतः खानापूरी वाली बात है। वास्तव में नियामक और सरकार दोनों अगर फिनटेक की चिंताओं को सुनकर नवाचार को बढ़ाने देने के लिए आवश्यक जरूरी समायोजन करें,तो बेहतर होगा। परंतु वर्तमान में इस संदर्भ में भी सरकार के कथनी और करनी में अंतर को देखा जा सकता है।

सरकार ने केंद्रीय वित्त सचिव टी वी सोमनाथन के अधीन एक विशेषज्ञ समिति गठित की है, ताकि 'अपने ग्राहकों को जानें'(केवाईसी)' मानकों को एकरूप बनाया जा सके। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर केवाईसी मानक एक क्यों हों? विविधता और नवाचार के लिए इसमें भी अलग–अलग स्वरूपों को क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता? क्या इस कमिटी में सरकार ने फिनटेक व नवाचार वाले अन्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों को स्थान दिया? सरकार अगर विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देती और समाधान का प्रयास करती, तो रास्ता निकलता, लेकिन कमिटी के उद्देश्य से ही स्पष्ट है कि नीति निर्माता केंद्रीयकृत व्यवस्था की सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ग्राहकों को जानने के मानकों में सुधार जरूर होना चाहिए,जिससे वित्तीय सेवा कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। परंतु इसके लिए इसके मानकों को ऐसा होना चाहिए, जो विविधताओं से सामंजस्य स्थापित कर सके।

जब केंद्रीय प्रसंस्करण ईकाइयां सस्ती हो गई और इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रसार हुआ तो 'फिनटेक क्रांति' को लेकर काफी उम्मीदें कायम हो गई। ऐसी सोच थी कि बैंकों का काफी कामकाज नए तरह की टेक्नालॉजी आधारित फर्मों से किया जा सकता है। इन नए फर्मों से उनका कामकाज बेहतर तरीके से हो पाएगा और देश में बैंकिंग का दायरा थोड़ा सिकुड़ता जाएगा। उदाहरण के लिए गूगल जैसी टेक्नालॉजी दिग्गज आसानी से भुगतान कार्य कर सकते हैं, एक ऐसा कारोबार जो कभी बैंकों का आधार था।

भारत के संदर्भ में फिनटेक क्रांति दो दृष्टिकोण से काफी बेहतर है। प्रथम– बैंकिंग भारत में प्रणालीगत जोखिम का स्रोत रहा है और छोटी बैंकिंग प्रणाली स्थिरता को बढ़ाती है। दूसराकृमौजूदा बैंक नवाचार और ग्राहक सेवा के मामलों में कमजोर हैं। ऐसे में फिनटेक टेक्नालॉजी और नवाचार के माध्यम से हमारे अर्थव्यवस्था के आधार बन सकते हैं। हमारे नीति निर्माताओं ने पिछले 10 वर्षों में केंद्रीय नियोजन प्रणाली का चयन कर फिनटेक को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेने दिया। नीति नियंता चाहते हैं कि 'फिनटेक कंपनियां' बैंकों की सेवा प्रदाता बनकर ही रहें। भारतीय बैंकिंग के अफसरशाही चरित्र और बैंकिंग में उत्पादों एवं प्रक्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण की वजह से भारत में बैंक संरचनात्मक रूप से खोज की प्रक्रिया में जुड़ने में अक्षम ही हैं। भारतीय गैर बैंकिंग कंपनियां समय और जोखिम की ऐसी समस्याओं को समाधान करने में बेहतर तरीके से उभरी हैं। यहां नए फिनटेक कंपनियों की भूमिका हो सकती थी। परंतु एनबीएफसी के फंडिंग समस्याओं से फिनटेक भी प्रभावित हुआ। भारतीय बॉन्ड बाजार की सीमाएं एनबीएफसी के वित्त पोषण के रास्ते में अड़चन हैं। आमतौर पर नीति नियंताओं ने एनबीएफसी की कीमत पर बैंकों को प्रोत्साहन दिया है।

वर्तमान में देश में सक्रिय 'सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यमों' के अस्तित्व के लिए पूंजी का अभाव सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। ऐसे में एमएसएमई क्षेत्र में फिनटेक की भूमिकाक्रांतिकारी हो सकती थी,जो उनके पूंजी की कमी को दूर कर सकती थी। कई फिनटेक स्टार्टअप द्वारा आसान और त्वरित ऋ ण उपलब्ध कराए जाने पर लघु उद्योगों को बैंकिंग जटिलताओं से मुक्ति मिल सकती है। परंतु वर्तमान में फिनटेक ही पूंजी की समस्या से ग्रस्त है।

क्या फिनटेक कंपनियों ने रिजर्व बैंक के समक्ष चुनौती उत्पन्न की है? यह चुनौती मूलतः बदलते टेक्नालॉजी के साथ स्वाभाविक है। कुछ फिनटेक कंपनियों ने यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस की मदद से भुगतान को सुगम बनाया है। वहीं बड़ी संख्या में ऐसी कंपनियां बैकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से ऋ ण को सुगम बना रही है। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता ऋ ण बहुत बढ़ गया। इस संदर्भ में रिजर्व बैंक ने गत नवंबर में उपभोक्ता ऋ ण का जोखिम भार बढ़ा दिया। इसके पीछे विचार था असुरक्षित ऋ ण वृद्धि की गति को धीमा करना। अब समय आ गया है कि नियामक भी अपने कार्यशैली में समयानुसार परिवतर्न लाएं। उनके नियंत्रण शैली में केंद्रीयकरण न हो तथा नवाचार का प्रयोग उन्हें भी करने की जरूरत है।

रिजर्व बैंक ने एल्गोरिदम आधारित ऋ ण में इजाफे को लेकर भी चिंता जताई है। अगर बिना समुचित जांच–परख के उपभोक्ता ऋण बढ़ाता है, तो इससे बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों दोनों को दिक्कत हो सकती है। यह देखा गया है कि कुछ उपभोक्ता एक से अधिक प्लेटफार्म से ऋ ण लेने में सक्षम हैं। हालांकि यह संभव है कि फिनटेक उन उपभोक्ताओं तक पहुंच रही हों, जो औपचारिक ऋ ण बाजार से बाहर हैं, लेकिन फिर भी तब तक सावधानी बरतना आवश्यक है जब तक कि इस पूरी प्रणाली और संभावित निष्कर्षों को अच्छी तरह समझ नहीं लिया जाता है। नवाचार और वृद्धि अनुमानों में संतुलन होना चाहिए, जिससे वित्तीय स्थिरता को मजबूती मिल सके। वित्त सभी उद्यमों में सबसे अहम है। यह अर्थव्यवस्था का मस्तिष्क है। फिनटेक क्रांति भारत के लिए काफी कुछ कर सकती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वित्तीय आर्थिक नीति की मौजूदा केंद्रीकृत व्यवस्था में बदलाव किया जाए।

सीएम योगी रखेंगे पशु चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला, देंगे 49 विकास परियोजनाओं की सौगात

गोरखपुर। सीएम योगी बृहस्पतिवार को गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। पशु चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला के साथ जिले में 1007 करोड़ रुपये की 49 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी तीन मार्च को गोरखपुर के ताल नदोर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। इसे भविष्य में विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसके एक दिन पहले दो मार्च को सीएम योगी महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जिले को 1007 करोड़ रुपये की 49 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।

गोरखपुर में बनने वाला पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय

पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा से संबद्ध होगा। इसके बन जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के पशुपालकों को भी काफी फायदा होगा। इस महाविद्यालय को क्रमवार तीन चरणों में विकसित किया जाएगा। इसके लिए गोरखपुर–वाराणसी हाईवे पर स्थित ताल नदोर में 80 एकड़ भूमि चिन्हित की जा चुकी है। पहले चरण के निर्माण पर 228 करोड़ रुपये की लागत आएगी। कार्यदायी संस्था के रूप में लोक निर्माण विभाग को जिम्मेदार दी गई है।

महाविद्यालय के परिसर में हॉस्पिटल ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, स्टाफ क्वार्टर, छात्रावास जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ–साथ पशु चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी विभिन्न विधाओं के शोध अध्ययन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। महाविद्यालय परिसर को 'नेट जीरो एनर्जी' की अवधारणा पर विकसित किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में यहां स्नातक स्तर पर 100 छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था होगी। ताल नदोर में मुख्यमंत्री तीन मार्च को दोपहर बाद महाविद्यालय के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे।

इसके एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां वह 1007 करोड़ रुपये की 49 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

इनमें करीब 954 करोड़ रुपये से अधिक की 35 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 53 करोड़ रुपये से अधिक की 14 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। लोकार्पण और शिलान्यास की परियोजनाओं में बाढ़ बचाव, फ्लाई ओवर, सड़क एवं नाली निर्माण, कलेक्ट्रेट परिसर में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण, एमईएस ऑफिस की शिफ्टिंग, पर्यटन विकास के कार्य सम्मिलित हैं।

प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी कराएं अमरमणि के संपत्तियों की कुर्की

बस्ती। बस्ती के व्यापारी के पुत्र राहुल मद्देशिया के अपहरण मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी भी नामजद आरोपी हैं। कोर्ट की तरफ से एनबीडब्लू और वारंट के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकी। कोर्ट ने कहा– आरोपी के प्रभावशाली होने के कारण उस पर कार्रवाई से स्थानीय पुलिस भी बच रही है।

बस्ती में एक व्यापारी के बेटे के अपहरण मामले में नामजद फरार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अमरमणि की संपत्तियों को कुर्क कराने में हीलाहवाली कर रही स्थानीय पुलिस को दरकिनार करते हुए न्यायालय ने अब प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को कार्रवाई के लिए कहा है। केस की अगली सुनवाई के लिए 20 मार्च को होगी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम/विशेष न्यायाधीश (एमपी–एमएलए कोर्ट) प्रमोद कुमार गिरि ने कहा कि ऐसी पूरी संभावना है कि स्थानीय पुलिस आरोपी के प्रभावशाली होने के कारण उस पर कार्रवाई करने से बच रही है। ऐसी स्थिति में समस्त जिलों में स्थित आरोपी अमरमणि त्रिपाठी की संपत्तियों की कुर्की के लिए प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया जाता है कि वे संपत्तियों को कुर्क कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई कराकर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का यहां ले सकेंगे लुत्फ, जल्द हो जाएगा तैयार

गोरखपुर। गोरखपुर के रामगढ़ताल में जल्द ले सकेंगे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुत्फ। बृहस्पतिवार को देर शाम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को रामगढ़ताल में उतारा गया था। सीएम योगी इसका लोकार्पण कर सकते हैं। गोरखपुर में लेक क्वीन क्रूज के बाद रामगढ़ताल में जल्द ही लोग फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में लजीज व्यंजन का लुत्फ उठा सकेंगे। लंबे इंतजार के बाद बृहस्पतिवार देर शाम करीब 7.30 बजे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को रामगढ़ताल में उतारा गया। इसके इंटीरियर का काम चल रहा है। काम पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण कर सकते हैं। 100 फीट लम्बाई और 33 फीट चौड़ाई के इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की क्षमता 150 लोगों की है। इसके अलावा 50 की संख्या में स्टाफ मौजूद रहेगा। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के निर्माण पर तकरीबन 10 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि बैठने के बाद इससे रामगढ़ताल का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का संचालन नया सवेरा पर बने प्लेटफार्म नम्बर 02 से किया जाएगा। फर्म के निदेशक रक्ष राजीव ढींगरा ने बताया कि उनकी कोशिश इसे मार्च मध्य में लोकार्पित कराने की है।

साढ़े तीन घंटे में मिली सफलता

बृहस्पतिवार शाम 4 बजे से फ्लोट को पानी में उतारने की कोशिशों में सफलता देर शाम 7.

30 बजे मिली। इस दौरान निदेशक रक्ष राजीव ढींगरा, जीएम उग्रसेन सिंह, जीएम फारेस्ट क्लब राहुल सिंह, जीएम रायल रेजिडेंसी राकेश राय, असरफ जमाल समेत सभी के चेहरे खिल उठे।

नवंबर 2022 से हो रहा था निर्माण

इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निर्माण नवंबर 2022 में शुरू हुआ। तकरीबन 200 टन वजन के इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के निर्माण में 10 करोड़ रुपये के करीब धनराशि खर्च हुई है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की मालिक लेकवर्स प्राइवेट लिमिटेड निदेशक रक्ष राजीव ढींगरा को गोरखपुर विकास प्राधिकरण को प्रतिमाह 4,52,500 रुपए एवं जीएसटी देना होगा। फर्म को फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के संचालन का अधिकार 15 साल के लिए मिला है।

100 से 150 रुपये में मिलेंगे लजीज व्यंजन

फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के प्रथम तल पर फूडकोर्ट होगा जिसमें 100 से 150 रुपये में विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजन उपलब्ध कराए जाएंगे। द्वितीय तल पर लग्जरी बार, रेस्टोरेंट, डिस्क की सुविधा रहेगी। ब्रेक फास्ट, लंच, हाई टी और डिनर उपलब्ध होगा। तृतीय तल ओपेन डेक होगा जिस पर पयर्टक सैर का आनंद ले सकेंगे। पार्टियां कर सकेंगे।

इसका संचालन सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक किया जाएगा। भीड़ को मैनेज करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। पयर्टकों की सुविधा के लिए दो लिफ्ट भी लगाई गई हैं। प्रथम और द्वितीय तल पूरा वातानुकूलित रहेगा।

सुरक्षा के साथ पर्यावरण का भी रखा गया है ध्यान

फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर सुरक्षा की दृष्टि से बाउंसर और लाइफ गार्ड की टीम मौजूद रहेगी। लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स के साथ फायर फाइटिंग सिस्टम भी उपलब्ध रहेगा। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जीरो वेस्ट मैनेजमेंट के तर्ज पर काम करेगा। यहां गीला एवं सूखा कचरा अलग–अलग एकत्र होगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि ताल में कचरा न जाए। बल्कि गीला एवं सूखा कचरा एकत्र कर उसे नगर निगम या जीडीए की कचरा उठाने वाली गाड़ियों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उचित ढंग से उसका निस्तारण हो। ताल की वनस्पतियों, जलीय जीव एवं पक्षियों मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए झील की बायोलॉजिकल सुरक्षा का ध्यान भी रखा जाएगा। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को रामगढ़ताल में उतारने में देर शाम सफलता मिल गई। अब उसके इंटीरियर का काम कराया जाएगा। 10 मार्च तक काम पूरा होने के बाद लोकार्पण कराया जा सकता है।

शेर कोठी के मकान को खाली कराने गई टीम लौटी अनशन पर बैठी महिला की हालत बिगड़ी

गोरखपुर। गोरखपुर कोतवाली थानाक्षेत्र के बक्शीपुर में शेर कोठी के एक मकान को लेकर विवाद चल रहा है। कब्जा करने का आरोप लगाने वाली रुपा अग्रवाल की तबीयत बृहस्पतिवार को अचानक से बिगड़ गई। परिजनों के साथ कब्जे के मुक्त करवाने की गुहार लगाने के साथ ही परिजन धरने पर बैठ गए हैं। आरोप है कि मकान खाली कराए गई टीम अचानक वापस लौट गई।

गोरखपुर के कोतवाली इलाके के बक्शीपुर शेर कोठी स्थित एक मकान को बृहस्पतिवार दोपहर 3:30 बजे खाली कराने गई प्रशासन की टीम लौट गई। मकान पर मालिकाना हक जताने वाली महिला और किराएदार के बीच विवाद है। मकान को अपना बताने वाली रूपा अग्रवाल आमरण अनशन पर बैठ गईं। देर शाम उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद बेटा उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गया। महिला ने न्याय न मिलने तक आमरण अनशन पर बैठने की बात कही है।

जानकारी के मुताबिक, राजघाट के

दीवान दयाराम की रहने वाली रूपा अग्रवाल पत्नी स्व. चंद्रप्रकाश अग्रवाल ने 2002 में भगवान भीटी गांव निवासी गंगा शरण सिंह को मकान किराए पर दिया था। वर्तमान में गंगा शरण के परिवार के राज नारायण सिंह का परिवार रहता है।

इसे लेकर रूपा अग्रवाल ने सीएम के जनता दर्शन में मुलाकात कर प्रार्थनापत्र दिया था।

सीएम के आदेश पर प्रशासन ने पूरे मामले की जांच की। बकौल रूपा अग्रवाल, बृहस्पतिवार को तहसीलदार ने जांच के बाद मकान को जब्त करने की बात कही थी। दोपहर में साढ़े तीन बजे के करीब तहसीलदार मौके पर गए और मकान को खाली करने के लिए कहे, लेकिन फिर वह लौट गए। इससे नाराज होकर रूपा अग्रवाल धरने पर बैठ गई।

उनकी मांग थी कि आज ही कार्रवाई को पूरी की जाए। जबकि, किराएदार का परिवार समय मांग रहा था। देर शाम महिला की तबीयत खराब हो गई।

बेटा लेकर अस्पताल चला गया। बेटे ने बताया कि वह डीएम और आला अफसरों से मुलाकात कर प्रार्थनापत्र देकर न्याय की गुहार लगाएंगे। डीएम कृष्णा करुणेश ने कहा कि मामले की जांच के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने जब्त करने का आदेश जारी किया है।

जिसके अनुपालन में प्रशासन की टीम गई थी।

मामला कोर्ट में भी है। प्रशासन नियमानुसार आवास को जब्त कराएगा। कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसका अनुपालन कराया जाएगा।

बेटी से अश्लील हरकत करने का आरोपी सौतेला पिता गिरफ्तार, रिश्ते को कर दिया शर्मशार

गोरखपुर। गोरखपुर में रिश्ते को शर्मशार करने की घटना सामने आई थी। बेटी ने आरोप लगाया कि पिता उसके साथ अश्लील हरकत करता है। सोमवार को भी उसके साथ छेड़खानी करते हुए बात नहीं मानने पर भाई और मां को जान मारने की धमकी देने लगा।गोरखनाथ इलाके में युवती से अश्लील हरकत करने के आरोपी सौतेले पिता को पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया।

जानकारी के अनुसार, गोरखनाथ क्षेत्र की रहने वाली युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि पिता उसके साथ अश्लील हरकत करता है। सोमवार को भी उसके साथ छेड़खानी करते हुए बात नहीं मानने पर भाई और मां को जान मारने की धमकी देने लगा। वह अक्सर मौका पाकर उसके साथ गलत हरकत करता है। अश्लील वीडियो भी जबरन दिखाता है और मना करने पर मारता पीटता है। उसकी पिटाई से आंख खराब हो गया है। पहले तो वह पिता की हरकतों को बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब हद पार करने लगा तो मजबूर होकर पुलिस से शिकायत की। गोरखनाथ थाने में आरोपी सौतेले पिता पर केस दर्ज किया गया है। सीओ गोरखनाथ योगेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी सौतेले पिता पर केस दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की है।

केंद्र के बड़े फैसले • पीएम सूर्य घर फ्री बिजली योजना मंजूर

सौर पैनल से मिलेगी 300 यूनिट बिजली; स्कीम से 17 लाख जॉब

सेमीकंडक्टर हब बनेगा भारत, 1.26 लाख करोड़ का निवेश, 3 यूनिट लगेंगी

– लखनऊ

केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को 75 हजार करोड़ रु. की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि योजना में निम्न आय और कम खपत वाले एक करोड़ घरों पर सोलर पैनल फ्री लगाए जाएंगे। ऐसे परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। आय ज्यादा है तो सोलर प्लांट लगाने के लिए 78 हजार रु. तक की सब्सिडी केंद्र सरकार देगी। इस स्कीम से करीब 17 लाख नए जॉब आएंगे। योजना के तहत हर जिले में एक मॉडल सौर गांव विकसित किए जाएगा।

इसके अलावा, 1.26 लाख करोड़ रु. में देश में पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब बनाया जाएगा। इसका निर्माण अगले 100 दिन में शुरू हो जाएगा।

वो सब कुछ, जो आपके लिए जानना जरूरी है

सोलर स्कीम के लिए एप्लाई कैसे करें?

pmsuryaghar.gov.in/ पर जाएं। एप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर के ऑप्शन पर क्लिक करें। रजिस्टेशन पेज खुलेगा। इस पर जानकारी भरें। फिर बिजली कंपनी से फिजीबिलिटी अप्रूवल मिलते ही रजिस्टर्ड वेंडर से संपर्क करें। इंस्टॉलेशन के बाद नेट मीटर के लिए आवेदन करें। मीटर लगने के बाद कंपनी की टीम निरीक्षण करेगी। कमीशनिंग सर्टिफिकेट देगी।

सब्सिडी कैसे मिलेगी?
कमीशनिंग रिपोर्ट मिलने के बाद पोर्टल से बैंक खाते का विवरण और एक कैंसिल चेक जमा करें। 30 दिन में सब्सिडी आ जाएगी।

कितना खर्च आएगा?

प्लांट	लागत	सब्सिडी
3 KW	1.45 लाख	78 हजार
2 KW	1.10 लाख	60 हजार
1 KW	50 हजार	30 हजार

▪ लागत की शेष राशि के लिए 7% ब्याज दर पर बैंक लोन मिलेगा।

पैसा कैसे कमा सकेंगे?
3 किलोवॉट से रोज 12 यूनिट बिजली बनती है। इससे 360 यूनिट महीने में बनेंगी। बची हुई यूनिट बिजली कंपनी को बेचकर सालाना 15 हजार तक कमा सकेंगे।

एक करोड़ घर कैसे चुनेंगे?
सरकार ऐसे घर चुनेगी, जहां खपत 300 यूनिट से कम है। ऐसे परिवारों का एक रुपए भी नहीं लगेगा। कम आय वाले पीएम आवास वालों को भी जोड़ने पर विचार।

जो पहले से रजिस्टर्ड, उनका क्या?
13 फरवरी 24 के पहले रूफटॉप सोलर एप्लीकेशन देने वालों को नई स्कीम के तहत लाभ नहीं मिलेगा।

पुरानी स्कीम का क्या होगा?
पुरानी सोलर स्कीम जारी रहेगी। नई में इससे 67% ज्यादा सब्सिडी है। पुरानी में 1 केवी पर 18 हजार, 2 केवी पर 36 हजार और 3 केवी पर 54 हजार रु. सब्सिडी है।

बिग कैट अलायंस बनाएगा भारत... केंद्र ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने को मंजूरी दे दी है। इसका मुख्यालय भारत में होगा। 7 बिग कैट यानी सिंह, शेर, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर, चीता का संरक्षण होगा।

मंत्री सूर्यप्रताप बोले– मोदी को रोकने के लिए चालीस चोर हो गए इकट्ठा

मायावती–अखिलेश को लेकर कही बड़ी बात

बागपत। बागपत पहुंचे कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि मोदी को रोकने के लिए चालीस चोर इक्ट्ठा हो गए है। वहीं, मायावती और अखिलेश को लेकर यह बड़ी बात कही। कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि हम कभी किताब में अलीबाबा चालीस चोर की कहानी पढ़ते थे। मगर आज अलग–अलग राज्यों के चालीस चोर इक्ट्ठा हो गए है कि मोदी को रोकना है। कहा कि आज एमएसपी के लिए शोर मचा रहे है, मगर जब तुमको मौका था तो तुमने क्यों एमएसपी लागू नहीं किया।

बागपत में एसपीसी डिग्री कॉलेज के मैदान पर किसान मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि अटल विहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए स्वामीनाथन कमेटी को गठित किया था। जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2006 में दी थी। लेकिन उसके बाद 2014 तक कांग्रेस के मनमोहन सिंह ने एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी। कहा कि वर्ष 2014 में धान पर 1310 रुपये प्रति क्विंतल एमएसपी था। गेहूं की एमएसपी 1400 रुपये प्रति क्विंतल थी। मोदी ने दस साल में 800 रुपये एमएसपी बढ़ाई।

पंजाब है असली किसान विरोधी और यूपी सरकार किसान समर्थक

कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में मंडी में फसल बेचने जाने पर दो प्रतिशत मंडी शुल्क और आधा प्रतिशत डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता था। योगी सरकार ने उसे घटाकर चार साल पहले ढाई से केवल डेढ़ प्रतिशत कर दिया। जबकि सब्जियों से मंडी शुल्क खत्म कर दिया गया। कहा कि पंजाब में मंडल में फसल बेचने जाते है तो साढ़े पांच प्रतिशत शुल्क लिया जाता है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि साढ़े पांच प्रतिशत शुल्क लेने वाला किसान समर्थक नहीं, बल्कि विरोधी है। वहीं, डेढ़ प्रतिशत वाला यूपी किसान विरोधी किस तरह है। वह किसान समर्थक है और यही सोच बदलनी है।

कांग्रेस ने चरण लसह को प्रधानमंत्री पद से हटाया, भाजपा ने भारत रत्न दिया

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह तक को कांग्रेस ने नहीं छोड़ा था। उनको प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए कांग्रेस ने केवल 21 दिन में समर्थन वापस ले लिया था। जबकि भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाए और उनको भारत रत्न देकर उनके साथ ही किसानों का सम्मान किया।

किसान की सालाना आय बढ़कर एक लाख रुपये हुई

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में किस तरह से बदलाव किया है, यह हर किसी को पता है। पहले जब हम आए थे, तब किसान की सालाना आय 45 हजार रुपये थी तो अब एक लाख तक पहुंचा दिया। आज 2275 रुपये प्रति क्विंतल गेहूं खरीद रहे है और फ्री खिलाने की हिम्मत किसी के पास है तो वह मोदी के पास है। पहली बार गन्ने का इतना पेमेंट कराया गया है। बागपत का इस साल का केवल 11 करोड़ रुपये गन्ना भुगतान बकाया है।

मायावती ने बेच दी शुगर मिल, अखिलेश ने बंद कर दी

कृषि मंत्री ने कहा कि मायावती ने 24 मिलों को बेच दिया। जितनी बच गई थी, उनको अखिलेश व मुलायम ने बंद कर दिया। 1962 की चीन की लड़ाई हम हार गए, 42 हजार वर्ग किमी जमीन पर आज भी चीन का कब्जा है। लेकिन जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई। तब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हमारे जवान मजबूती से लड़े। तब लाहौर तक पहुंच गए थे।

गन्ने के साथ दूसरी फसलों की खेती पर जोर दिया

सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि कृषि मंत्री कभी दोबारा चुनाव नहीं जीत सका, लेकिन मैंने काम किया तो मुझे दोबारा जीत मिली। कहा कि देश का 40 फीसदी आदमी आज शुगर का मरीज हो गया है।

इसलिए यह सोचना होगा कि गन्ने के साथ दूसरी खेती की तरफ भी रुख करना है। क्योंकि इस तरह हमारे बच्चे आगे भी बीमार होंगे। अनाज के बिना क्या चीनी खाकर जीवन चल सकता है। कहा कि इस क्षेत्र की जियो टैगिंग बासमती की पैदावार के लिए है। कहा कि लैब की जगह किसान के खेत में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है।

यूपी में सहयोगी दलों को छह सीटें देगी भाजपा

राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ेंगे चुनाव!

लखनऊ। यूपी में भाजपा सहयोगी दलों को छह सीटें दे सकती है। वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से ही चुनाव लड़ेंगे। जल्द की इसकी घोषणा की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी में सभी 80 सीटों पर जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा प्रदेश में सहयोगी दलों को छह सीटें दे सकती है। चुनाव की तैयारियों को लेकर बृहस्पतिवार को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा यूपी में रालोद को दो सीटें, अपना दल को दो सीटें, निषाद पार्टी को एक सीट और राजभर की पार्टी सुभासपा को एक सीट दे सकती है। वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले शुक्रवार या शनिवार को सौ से अधिक उम्मीदवारों की सूची और 10 मार्च तक करीब 250 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे।

केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पूर्व प्रधानमंत्री निवास पर पार्टी के शीर्ष नेताओं की करीब छह घंटे तक चली बैठक में 21 राज्यों की 300 सीटों पर उम्मीदवारो का पैनल तैयार कर लिया गया है। इस बैठक में पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गठबंधन पर बातचीत तय होने तक उम्मीदवार घोषित नहीं करने का फैसला किया गया है।

अब रोडवेज बस से जाइए अयोध्या से हरिद्वार

लखनऊ। राजस्थान सहित चार प्रांतों ने अयोध्या से बस सेवा शुरू कर दी है। राज्य स्तरीय बातचीत के बाद संचालन अयोध्या से अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू हो गई है। राजस्थान सहित चार प्रांतों ने राज्य स्तरीय बातचीत के बाद रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया है। विगत 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इसके बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के रोडवेज महकमों ने अयोध्या तक बसों के संचालन में दिलचस्पी दिखाई। कुछ के अफसरों ने फोन से यहां के रोडवेज के अफसरों से बात की, जबकि हरियाणा की टीम यहां पहुंची थी।

विभाग ने अन्य प्रदेश के अफसरों को बताया था कि राज्य स्तरीय समझौते या फिर परमिट के आधार पर बसों का संचालन शुरू हो सकता है। बातचीत के बाद चारों प्रांतों ने अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू कर दी। बस सेवा अलग–अलग दिन से शुरू हुई। बसों का अयोध्या धाम स्टेशन से आवागमन होने लगा हैं। रोडवेज ने यहां से उत्तराखंड के हरिद्वार के लिए भी बस सेवा शुरू की है। हरिद्वार के लिए बस सुबह 10 बजे छूटती है। अयोध्या से हरिद्वार की दूरी 745 किमी. है और किराया 1075 रुपये है। टनकपुर के लिए अभी बस सेवा नहीं शुरू की गई है, जल्द ही यह सेवा भी शुरू होने की संभावना है। एआरएम आदित्य प्रकाश ने बताया कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड प्रदेश से बस सेवा शुरू हुई है। इन प्रदेशों के रोडवेज महकमों ने सेवा शुरू की है। अयोध्या से हरिद्वार के लिए बस सेवा की शुरुआत कर दी गई। टनकपुर के लिए बसों का संचालन अभी नहीं शुरू हुआ है।

पहले चरण में 81 हजार बच्चों को स्कूल आवंटित, जांच में 1.37 लाख सही मिले

इस तरह बढ़े आवेदन

– 2021–22 में तीन चरण में दो लाख 98 आवेदन, 1.53 लाख आवेदन सही, 99255 को स्कूल आवंटित
– 2022–23 में तीन चरण में 2.51 लाख आवेदन, 1.94 लाख आवेदन सही, 1.24 लाख को स्कूल आवंटित
– 2023–24 में तीन चरण में 2.85 लाख आवेदन, 2.8 लाख आवेदन सही, 1.34 लाख को स्कूल आवंटित
– 2024–25 में पहले चरण में 1.82 लाख आवेदन, 1.37 लाख आवेदन सही, 81 हजार को स्कूल आवंटित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देश दिया है कि सभी बीएसए स्कूल आवंटन होने वाले बच्चों का जिला स्तर पर अभियान चलाकर प्रवेश सुनिश्चित कराएं। दूसरे चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन एक से 30 मार्च तक लिए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में कमजोर आय वर्ग के बच्चों के निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत गत वर्ष की अपेक्षा काफी अच्छा रुझान है। निजी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक व कक्षा एक में 25 फीसदी तक प्रवेश के लिए पहले चरण में 1.82 लाख आवेदन हुए। इसमें जांच में 1.37 हजार आवेदन सही पाए गए और जिला स्तर पर हुई लॉटरी में पहले चरण में 81,816 बच्चों को स्कूल आवंटित किए गए हैं।शासन ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि स्कूल आवंटन होने वाले बच्चों का जिला स्तर पर अभियान चलाकर प्रवेश सुनिश्चित कराएं। दूसरे चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन एक से 30 मार्च तक लिए जाएंगे। इस साल शासन चार चरण में आरटीई के तहत आवेदन लेकर बच्चों के प्रवेश सुनिश्चित कराएगा।शासन ने आरटीई के तहत होने वाले प्रवेश की प्रतिपूर्ति के लिए बजट प्रावधान 181 करोड़ से बढ़ाकर 308 करोड़ किया है।

वहीं पिछले कई सालों के बकाया प्रतिपूर्ति शुल्क का भी इस साल भुगतान कर दिया गया है। यही वजह है कि इसमें विद्यालय भी रुचि ले रहे हैं। इस साल आरटीई में रजिस्टर्ड स्कूलों की संख्या भी बढ़ी है। शासन ने इस साल प्रवेश का लक्ष्य भी बढ़ाकर दो लाख किया है, जबकि गत वर्ष 1.1 लाख बच्चों का प्रवेश हुआ था।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने बताया कि स्कूलों में सीट क्षमता के अनुसार पहले चरण में 81 हजार विद्यालय आवंटित हुए हैं। जो बच्चे इस चरण में छूट गए हैं, वह अगले चरण में फिर से दूसरे स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला स्तर पर, तहसील व ब्लॉक में भी विभिन्न माध्यमों से आरटीई का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें।

पूर्व आईजी ने लिखी डान
श्रीप्रकाश शुक्ला के अंत की कहानी

90 के दशक के आपराधिक कालखंड की सच्ची दास्तान है 'वर्चस्व'

लखनऊ। नब्बे के ही दशक में जब दिन–दहाड़े सरेआम हत्या होने लगी। माफिया का काफिला जिधर से गुजर जाता सड़कें अपने खाली हो जाया करती थीं। उन्हीं दिनों की पैदावार गोरखपुर के श्रीप्रकाश शुक्ला के आतंक ने यूपी और बिहार में सबकी नींदें उड़ा दी थीं। गोरखपुर में केबल के धंधे में पैर जमाने के लिए एक हफ्ते में ही एक–एक कर दर्जन भर लोगों को मार डाला था।

पूर्व आईजी ने लिखी डॉन श्रीप्रकाश शुक्ला के अंत की कहानी, 90 के दशक के आपराधिक कालखंड की सच्ची दास्तान है 'वर्चस्व'

1997 में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही को गैंगस्टर श्रीप्रकाश शुक्ला ने दिनदहाड़े मौत के घाट उतार दिया था।

सतीश पांडेय, गोरखपुर। 1993 में पहली हत्या कर अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला 20 साल के नौजवान आने वाले कुछ वर्षों में यूपी से लेकर बिहार तक आतंक कायम कर दिया। अपहरण हो या जबरन वसूली, रेलवे के ठेकों के वर्चस्व की जंग हो या फिर कबाड़ नीलामी का ठेका... हर जगह गोरखपुर के श्रीप्रकाश शुक्ला का सिक्का चलता था। उसकी आंखों में किसी का भय नहीं था। किसी के लिए दया नहीं थी। वह ऐसा बेदर्द इंसान था जिसने धंधा जमाने के लिए हत्या पर हत्या कर डाली। यूपी एसटीएफ के संस्थापक सदस्य के साथ ही श्रीप्रकाश को मुठभेड़ में ढेर करने वाली टीम का हिस्सा रहे पूर्व आइजी राजेश पाण्डेय ने अपनी पुस्तक 'वर्चस्व' में इस दुर्दांत अपराधी के उदय से अंत तक का पूरा किस्सा बताया है।

नब्बे के ही दशक में जब दिन–दहाड़े सरेआम हत्या होने लगी। माफिया का काफिला जिधर से गुजर जाता, सड़कें अपने खाली हो जाया करती थीं। उन्हीं दिनों की पैदावार गोरखपुर के श्रीप्रकाश शुक्ला के आतंक ने यूपी और बिहार में सबकी नींदें उड़ा दी थीं। गोरखपुर में केबल के धंधे में पैर जमाने के लिए एक हफ्ते में ही एक–एक कर दर्जन भर लोगों को मार डाला था।

श्रीप्रकाश शुक्ला ने अत्याधुनिक हथियारों से वीरेंद्र शाही समेत चार बड़े हत्याकांड अंजाम देकर पुलिस–प्रशासन सहित सरकार को खुली चुनौती दे डाली थी। सामने चाहे कितना भी रसूखदार आदमी हो, उस पर गोली चलाने में श्रीप्रकाश के हाथ नहीं कांपते थे। उससे निपटने के लिए चार मई, 1998 को यूपी पुलिस के तीन अधिकारियों की देखरेख में एसटीएफ का गठन हुआ, जिसमें पूर्व आइजी राजेश पांडेय भी शामिल रहे।

एसटीएफ ने पुलिस महकमे में इलेक्ट्रानिक सर्विलांस की शुरुआत की। इसी के बल पर 22 सितंबर, 1998 को गाजियाबाद में श्रीप्रकाश शुक्ला और उसके दो साथियों को मुठभेड़ में मार गिराया। लंबे समय तक श्रीप्रकाश की निगरानी करने वाले राजेश पांडेय ने अपनी किताब में लिखा है कि वह टार्गेट को हिट करने से पहले रेकी कराता था, जिसे वह कुंडली कहता था। इसके लिए उसने करीब दर्जन भर पढ़ने वाले लड़कों को रखा हुआ था। 296 पेज की यह पुस्तक राधाकृष्ण पेपरबैक्स ने छापी है।

खाता हैक कर 51.88 लाख निकाले

अब बैंक को देने होंगे 74.25 लाख

धोखाधड़ी में बैंक कर्मचारियों की भूमिका!

लखनऊ। कारोबारी का खाता हैक कर 51.88 लाख रुपये निकाल लिए। मामला राज्य उपभोक्ता आयोग में पहुंचा। आयोग का आदेश है कि अब बैंक को 74.25 लाख रुपये देने होंगे। धोखाधड़ी में बैंक कर्मचारियों की भूमिका से भी इन्कार नहीं किया है।

लखनऊ के कारोबारी सोमनाथ चटर्जी के बैंक खाते से 51.88 लाख रुपये धोखेबाजी से निकाल लिए गए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे खाताधारक की लापरवाही बताकर यह रकम देने से इन्कार कर दिया। कारोबारी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की।

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने आदेश दिया कि बैंक ऑफ बड़ौदा सोमनाथ को 51.88 लाख रुपये 10 फीसदी सालाना ब्याज के साथ वापस करे। मानसिक कष्ट के रूप में 10 लाख रुपये और वाद व्यय के रूप में 25 हजार रुपये भी बैंक को देने के आदेश दिए। इस तरह धोखाधड़ी के शिकार खाताधारक को करीब 74.25 लाख रुपये मिलेंगे। आयोग ने कहा कि इस धोखाधड़ी में बैंक कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है। हो सकता है कि उन्होंने ही खाता हैक कर लिया हो। लखनऊ में आशियाना निवासी सोमनाथ चटर्जी मुद्रा मार्केटिंग के प्रोपराइटर हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की नरही शाखा में उनका बचत खाता, चालू खाता और 50 लाख रुपये का ओवरड्राफ्ट खाता है। ओवरड्राफ्ट खाते के एवज में उन्होंने बैंक में 60 लाख रुपये की एफडी कराई है। ओवरड्राफ्ट खाते से लेनदेन केवल ओटीपी के जरिये ही किया जा सकता है। 25 मार्च 2021 की रात उनका मोबाइल फोन बंद था। अगले दिन सुबह उन्हें पता चला कि उनके एक खाते से 1.89 लाख और ओवरड्राफ्ट खाते से 49.99 लाख रुपये निकल गए। इतनी बड़ी रकम निकासी से पहले न तो उनके फोन पर ओटीपी आया, न ही पुष्टि के लिए एसएमएस आया, न ही कोई कॉल आई और न ही ईमेल किया गया। उन्होंने तत्काल बैंक में सूचना दी। साइबर फ्रॉड सेल में एफआईआर दर्ज कराई। बैंक ने जांच के बाद ठीकरा सोमनाथ चटर्जी पर ही यह कहते हुए फोड़ दिया कि ओटीपी और मैसेज किए गए थे इसलिए फ्रॉड के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है। सोमनाथ ने बैंकिंग लोकपाल में भी शिकायत दर्ज कराई लेकिन राहत नहीं मिली। राज्य उपभोक्ता आयोग ने इस मामले पर कोई फैसला सुनाने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का अध्ययन किया। इसमें पाया गया कि साइबर फ्रॉड के मामले में ग्राहक से ज्यादा बैंकों की जिम्मेदारी है। जिन मामलों में न ग्राहक की लापरवाही पाई जाती है और न ही बैंक की, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में कमी पाई जाती है तो ग्राहक को नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। बैंकों को अपना सिस्टम फूलप्रूफ बनाना चाहिए। आयोग ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस मामले में बैंक की सेवाओं में कमी पाई है। आयोग ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बैंक के कर्मचारियों ने धोखेबाज के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ–साथ शिकायतकर्ता के खाते को कुछ मिनटों के लिए हैक कर लिया होगा।

जौनपुर में नितिन गडकरी

10 हजार करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात

जौनपुर को मुंबई जैसा बनाने की कही बात

जौनपुर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जौनपुर दौरे पर हैं। इससे पहले वे मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम गए। वहां दर्शन पूजन करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। जौनपुर जिले में कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात भी दी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को दोपहर 2.23 बजे जौनपुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने जिले को करीब 10 हजार करोड़ की दस बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। इसके बाद विशाल जनसभा में केंद्रीय मंत्री का संबोधन शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि जौनपुर से करीब दस हजार करोड़ की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास आज किया गया है। उत्तर प्रदेश में 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग की लेंथ 7643 किमी थी, जो आज 13 हजार किमी है।

गडकरी ने कहा कि जौनपुर से प्रयागराज तक तीन बाईपास का निर्माण होगा। आजमगढ़ में बाईपास जून 24 तक शुरू होगा। मुंगरबादशाहपुर बाईपास जून 24 तक शुरू होगा। कहा कि राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी द्वारा शहर की सड़कों के सुदृढिकरण की मांग पूरी की जाएगी। दोनों किनारों पर आरसीसी सर्विस लेन और स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। जौनपुर स्टेशन के पास विकास कार्य किए जाएंगे। ओवरब्रिज के पास सर्विस लेन बनवाएंगे। कहा कि बनारस से लुंबिनी तक 1100 किमी की परियोजना को पूरा किया।

चमकेंगी जौनपुर की सड़कें: सीमा द्विवेदी

इससे पहले राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जौनपुर जिले को मिली सौगात से यहां की सड़कें अब चमकेंगी। मुंगराबादशाहपुर बाईपास रोड बाईपास से यातायात सुगम होगा। कहा कि पूर्वांचल में सड़कों का जो जाल बिछा है, वह नितिन गडकरी की देन है। वे जो कहते हैं उसे करते भी हैं। अब जौनपुर की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस दौरान प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि मछलीशहर में आगमन के दौरान रिंग रोड की मांग की थी वो पूरी हुई। जौनपुर को जाम से निजात दिलाने का काम किया। फ्लाईओवर की भी सौगात दी।

प्रतिबंध लगने के बाद भी जमा कर ली ईंट भट्ठों की रायल्टी

अलीगढ़। दो तहसील क्षेत्रों में जिगजैग तकनीक दूर–दूर तक न मिलने व साधारण तरीके से भट्ठे चलते मिले हैं। खैर, इगलास, अतरौली तहसील क्षेत्र में सात भट्टे जांच में ऐसे मिले जो साधारण तकनीक से संचालित हो रहे थे। अलीगढ़ जिले में ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) व प्रशासन के निर्देश के बावजूद नियम खिलाफ संचालित ईंट भट्ठों के प्रकरण में जिलाधिकारी विशाख जी ने जांच बिठा दी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रशासन को जिगजैग तकनीक वाले भट्ठों के संचालित होने की सूची भेजी है। दो तहसील क्षेत्रों में जिगजैग तकनीक दूर–दूर तक न मिलने व साधारण तरीके से भट्ठे चलते मिले हैं। खैर, इगलास, अतरौली तहसील क्षेत्र में सात भट्टे जांच में ऐसे मिले जो साधारण तकनीक से संचालित हो रहे थे। एडीएम वित्त मीनू राणा ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है। जिन सौ से अधिक भट्ठों की सूची प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रशासन को भेजी है। करीब 40 भट्ठों की रॉयल्टी खनन विभाग के पोर्टल पर जमा हो गई। दोनों विभाग एक–दूसरे की गलती ठहरा रहे हैं। खनन विभाग का कहना है कि वह सिर्फ खनन, ईट पथाई के एवज में रॉयल्टी जमा कराता है। संचालन का कोई लेना देना नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि जब पूर्व में सूची भेजी जा चुकी है कि भट्ठों का संचालन नहीं किया जा सकता है। फिर भी रॉयल्टी किस आधार पर जमा करा ली गई।

शादी शून्य होने पर भी पत्नी कर सकती है घरेलू हिंसा का केस

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक मामले में पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अलग होने से पहले पति–पत्नी साथ रह रहे थे ऐसे में घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 क तहत दाखिल परिवाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा है कि विवाह शून्य घोषित होने पर भी पत्नी घरेलू हिंसा का मुकदमा कर सकती है। शादी को समाप्त होने से घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत दाखिल परिवाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह फैसला व आदेश पति की याचिका पर दिया।

प्रतापगढ़ जिले के इस मामले में याची पति का कहना था कि उसकी और शिकायतकर्ता पत्नी की शादी को 26 मार्च 2021 को परिवार न्यायालय ने डिक्री पारित करते हुए शून्य घोषित कर दिया है। ऐसे में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि अलग होने से पूर्व याची व विपक्षी पति–पत्नी की तरह ही रह रहे थे और एक घरेलू नातेदारी में थे।

ऐसे में पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पीड़िता मानी जाएगी और धारा 12 के तहत परिवाद दाखिल करने का पूर्ण अधिकार है। इस विधिक व्यवस्था के साथ कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज कर दिया।

यूपी बोर्ड का 'पेपर लीक' से इनकार परीक्षा शुरू होने के एक घंटे बाद शेयर होने पर 'पेपर लीक' कैसे

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से आधिकारिक तौर पर 'पेपर लीक' होने की किसी भी घटना से इनकार किया गया है। बता दें कि यूपी बोर्ड द्वारा इंटर मैथ और बायो के प्रश्नपत्रों का आयोजन 29 फरवरी 2024 को किया गया। दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से आयोजित इन दोनों विषयों की परीक्षाओं के प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के दावे किए जा रहे हैं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2023–24 के लिए हाई स्कूल (कक्षा 10) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12) की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में, यूपी बोर्ड द्वारा कक्षा 12 परीक्षार्थियों के लिए गणित और जीव विज्ञान के प्रश्नपत्रों का आयोजन बृहस्पतिवार, 29 फरवरी 2024 को किया गया। हालांकि, दूसरी पाली यानी दोपहर 2 बजे से आयोजित इन दोनों विषयों की परीक्षाओं के प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच यूपी बोर्ड की तरफ से आधिकारिक तौर पर 'पेपर लीक' होने की किसी भी घटना से इनकार किया गया है। न्ब्डैच् सचिव दिब्यकांत शुक्ल द्वारा आज यानी शुक्रवार, 1 मार्च 2024 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक इंटर मैथ और बायोलॉजी के पेपर दोपहर 2 बजे से आयोजित किए गए थे, जबकि सोशल मीडिया पर इनके प्रश्न–पत्र दोपहर 3.15 बजे साझा किए गए थे।

ऐसे में बोर्ड के अधिकारियों की कहना है कि जब परीक्षा शुरू होने के एक घंटे बाद व्हाट्सऐप या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यदि प्रश्न पत्र शेयर किए गए तो इसे 'पेपर लीक' कैसे कहा जा सकता है। हालांकि, इसके बावजूद **UPMSP** द्वारा इस मामले की जांच किए जाने और दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी गई।

बता दें कि यूपी बोर्ड इंटर मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर दोपहर 3.11 बजे 'आल प्रिंसिपल आगरा' नाम के एक व्हाट्सऐप्प ग्रुप पर विनय चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने वाट्सऐप नंबर 9897525748 से साझा किए थे। हालांकि, इस व्यक्ति ने पेपर शेयर करने के 5 मिनट में ही इन्हें डिलीट भी कर दिया था, लेकिन इस बीच क्वेश्चन पेपर अन्य ग्रुप्स में फॉरवर्ड होता गया।

जिस व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया गणित और जीव विज्ञान के पेपर उसके एडमिन हैं पूर्व डीआईओएस

आगरा। आगरा में गणित और जीव विज्ञान के प्रश्नपत्र जिस व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुए हैं, उसके ग्रुप एडमिन पूर्व डीआईओएस मनोज कुमार हैं। ग्रुप में शिक्षक और प्रधानाचार्य सदस्य हैं। प्रश्नपत्र वायरल होने के बाद दो एडमिन ग्रुप से हट गए। इस ग्रुप पर प्रश्नपत्रों की फोटो वायरल की गई। पहली बार विनय चौधरी के नंबर से वायरल की गई। उसके बाद एक अन्य सदस्य ने वायरल की।

प्रश्नपत्र के निरस्त होने पर असमंजस

माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। प्रश्नपत्रों के फोटो वायरल होने से परीक्षा की शुचिता को लेकर स्थिति साफ नहीं की गई है। परीक्षार्थियों के मन में परीक्षा को लेकर असमंजस बना है। परीक्षा निरस्त न कर दी जाए। हालांकि इस बारे में शिक्षा अधिकारियों की तरफ से कोई स्थिति साफ नहीं की गई है।

इन सवालों के नही मिले जवाब

– प्रश्नपत्रों को व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल करने का मकसद क्या है। परीक्षा केंद्र पर उत्तरपुस्तिका बदलने का खेल तो नहीं चल रहा।
– किसी भी सचल दल ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण नहीं किया।
– परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल कैसे ले जाने दिया गया।
– क्या प्रश्नपत्र के फोटो एक ग्रुप पर वायरल किए गए या उससे पहले किसी और पर भी हुए।

ऐसी कार्रवाई जो भविष्य में नजीर बनेगी

जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि पेपर लीक मामले के आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में कार्रवाई नजीर बनेगी।

यूपी में सहयोगियों के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी भाजपा? रालोद–सुभासपा को मिल सकती हैं इतनी सीट

नोएडा। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां मंथन करने में जुटी हैं। यूपी में भाजपा सहयोगी दलों के लिए छह सीटें छोड़ सकती है। दिल्ली में गुरुवार को हुई भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक में सीटों पर मंथन हुआ। आगामी लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक के साथ 370 सीटें जीतने का लक्ष्य तय करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी दलों के लिए सीटें देने के लिए मंथन हुआ। गुरुवार को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक से पूर्व प्रधानमंत्री निवास पर पार्टी के शीर्ष नेताओं की करीब छह घंटे तक बैठक चली।

इस बैठक में 21 राज्यों की 300 सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर लिया गया। हालांकि इस बैठक में पंजाब, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु में गठबंधन पर बातचीत तय होने तक उम्मीदवार घोषित नहीं करने का फैसला किया गया।

सहयोगी दलों को छह सीटें दे सकती है भाजपा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों में से भाजपा यूपी में सहयोगी दलों को छह सीट छोड़ सकती है। इसमें राष्ट्रीय लोकदल दो सीटों मिल सकती हैं, रालोद के अलावा अपना दल पार्टी भी दो सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जबकि निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुभासुपा के लिए एक–एक सीट छोड़ी जा सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

आपको बता दें कि पीएम की अगुवाई में हुई मैराथन बैठक के बाद पार्टी मुख्यालय में देर रात सीईसी की बैठक शुरू हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों को सीटें देने पर मंथन हुआ। बैठक में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, असम, झारखंड, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, अंडमान निकोबार, ओडिशा, दिल्ली, मणिपुर, जम्मू–कश्मीर की सीटों पर मंथन हुआ। इनसे जुड़ी करीब 300 सीटों पर तीन–तीन उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया गया। पार्टी की योजना एक या दो मार्च को पहली सूची जारी करने और दस मार्च तक तीन सौ सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की है।

दिल्ली की चार सीटों पर नए चेहरों को उतारने की तैयारी

आगामी लोकसभा चुनाव में राजधानी दिल्ली के मतदाता भाजपा की ओर से नए चेहरों का दीदार करेंगे। बीते चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा इस बार राजधानी की सात में से कम से कम चार सीटों पर नए चेहरों को मौका देगी। पार्टी नेतृत्व ने इस बार मनोज तिवारी, रमेश विधूड़ी और प्रवेश वर्मा को ही दोबारा मौका देने का मन बनाया है।

दोपहर में बनी दुल्हन... शाम को उजड़ गई मांग

दूल्हे की मौत: शादी के तीन घंटे बाद उजड़ गया दुल्हन का सुहाग, घर जाते वक्त रास्ते में हुआ दर्दनाक हादसा

बरेली। बदायूं के बिसौली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में जितेंद्र और प्रियंका की शादी हुई थी। दोनों खुशी–खुशी घर लौटे, लेकिन रास्ते में हुए एक हादसे ने दोनों परिवारों की सारी खुशियां छीन लीं। बदायूं के इस्लामनगर क्षेत्र में ऐसा हादसा हुआ, जिसने दो परिवारों की खुशियां छीन ली। शादी के चंद घंटे बाद ही प्रियंका का सुहाग छिन गया। उसके पति की घर आते समय सड़क हादसे में मौत हो गई।

इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव चांदपुर निठाया निवासी जितेंद्र (22) पुत्र जसवंत सिंह की शादी बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव जलालपुर निवासी प्रियंका के साथ तय हुई थी। बृहस्पतिवार दोपहर को बिसौली कस्बे के मदनलाल इंटर कॉलेज में सामूहिक विवाह योजना के तहत कई युवक युवतियों की शादी कराई गई। इसी में जितेंद्र और प्रियंका की शादी हुई थी।

जितेंद्र अपनी मां अनारकली और गांव के धारा सिंह के साथ आया था। दूसरी ओर से प्रियंका के मायके वाले शामिल हुए थे। शादी के बाद शाम चार बजे प्रियंका अपने मायके वालों के साथ ससुराल चली गई जबकि जितेंद्र, उसकी मां और धारा सिंह अलग–अलग बाइक पर गांव लौट रहे थे। उस दौरान जितेंद्र हेलमेट लगाए था।

काफी दूर तक घिसटती रही बाइक

बताते हैं कि उनकी दोनों बाइक कुढ़ौली मोड़ पर पहुंची थी। तभी सामने से आ रही आलू लदी ट्रैक्टर–ट्रॉली की चपेट में जितेंद्र की बाइक आ गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रैक्टर–ट्रॉली के बीच में जितेंद्र की बाइक फंस गई और काफी दूर तक घिसटती चली गई।

हादसे में जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसकी मां और धारा सिंह घायल हो गए। इस हादसे की चपेट में एक और बाइक सवार आ गया लेकिन वह बाल–बाल बच गया और बाद में अपनी बाइक लेकर चला गया। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। बाद में ट्रैक्टर–ट्रॉली कस्बे में लेकर युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया।

रो–रोकर प्रियंका हुई बेसुध

चांदपुर निठाया निवासी जितेंद्र दो भाइयों में बड़ा था। वह खेतीबाड़ी करता था। बृहस्पतिवार को सामूहिक विवाह में उसकी शादी प्रियंका के साथ हुई थी। यहां केवल चंद लोगों के लिए बुलाया गया था। कोई बरात या बैंडबाजा लाने की व्यवस्था नहीं थी। केवल दूल्हा–दुल्हन और परिवार के गिनेचुने लोगों को बुलाया गया था। इससे उनके परिवार के लोग ही शामिल हुए थे। जितेंद्र की मौत से उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति की मौत की खबर मिलते ही प्रियंका रो–रोकर बेसुध हो गई। उसके आंसू नहीं थम रहे थे।

राम मंदिर निर्माण के बाद जातीय सीमाओं से ऊपर उठा यूपी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राम मंदिर निर्माण के बाद जातीय सीमाओं से ऊपर उठ गया है। अब आरएसएस ने 58 प्रतिशत वोट हासिल करने का लक्ष्य दिया है। संघ और अनुषांगिक संगठनों की पूरी टीम चुनाव में जुटेगी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह सर कार्यवाह अरुण कुमार ने कहा कि अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर स्थापित राममंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूपी जातीय सीमाओं से बाहर ऊपर उठ गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई दल जाति आधारित राजनीति करता है तो करता रहे।

भाजपा को जाति की दीवारों को तोड़कर समग्र समाज एवं प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। सुल्तानपुर में बृहस्पतिवार को आयोजित भाजपा के काशी और गोरखपुर क्षेत्र की समन्वय बैठक में उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को 58 से 60 फीसदी वोट हासिल करने का लक्ष्य दिया।

प्रदेश सरकार के मंत्रियों और भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक में अरुण कुमार ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में सभी जाति और समाज के लोगों ने सहयोग किया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन भी सभी जातियों के लोग पूरी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ में मग्न रहे। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि अब यूपी में जाति या समाज कोई मुद्दा नहीं हैं। विपक्षी दल जाति के नाम पर लोगों को भड़का नहीं सकते। उन्होंने कहा कि भाजपा और अनुषांगिक संगठनों को अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सभी को साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम करना है।

राष्ट्रवाद और लहदुत्व के मुद्दे को घर–घर पहुंचाएंगे

लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा के मिशन 80 को पूरा करने के लिए बूथ स्तर तक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दा बनाने में संघ पूरी ताकत लगाएगा। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की स्थापना, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर निर्माण और जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति जैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे हथियार बनेंगे।

प्रदेश सरकार के मंत्रियों और भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक में अरुण कुमार ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में सभी जाति और समाज के लोगों ने सहयोग किया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन भी सभी जातियों के लोग पूरी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ में मग्न रहे। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि अब यूपी में जाति या समाज कोई मुद्दा नहीं हैं। विपक्षी दल जाति के नाम पर लोगों को भड़का नहीं सकते। उन्होंने कहा कि भाजपा और अनुषांगिक संगठनों को अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सभी को साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम करना है।

ये कैसी मोहब्बत, प्रेमिका बनी कातिल

शादी के शोर में दब गई प्रेमी की चीखें.. गला दबाया, फिर कार में जला दी लाश

:आगरा। एक प्रेमी को मोहब्बत का ऐसा सिला मिला, जिसे जानकर लोगों की रूह कांप गई। प्रेमिका संग मिलकर पिता और मां ने गला दबाकर प्रेमी की हत्या की। इसके बाद कार में लाश को डालकर आग लगा दी। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमिका और उसकी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कासगंज के ट्रांसपोर्ट कारोबारी पुष्पेंद्र यादव की हत्या में आरोपी हिस्ट्रीशीटर अवधेश यादव की बेटी डॉली और उसकी मां भूरी देवी को पुलिस ने बृहस्पतिवार को जेल भेज दिया। इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 25 फरवरी की रात घर में शादी थी। उसी में पुष्पेंद्र यादव को फोन कर बुलाया था। इस दौरान मौका पाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। शादी समारोह में शोर होने के कारण किसी को कुछ पता नहीं चल सका। देर रात रिश्तेदारों के जाने के बाद शव को कार सहित ठिकाने लगाने के लिए फरह के रास्ते राजस्थान जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसे कार सहित जला दिया।

एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर रैपुराजाट के पास से भूरी देवी पत्नी अवधेश और उसकी बेटी डॉली निवासीगण ग्राम ककरैटा, सिकंदरा, आगरा को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान भूरी देवी ने बताया कि पुष्पेंद्र यादव निवासी आवास विकास, कासगंज, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता था, उसके पति अवधेश यादव से अच्छे संबंध थे। घर आने–जाने के दौरान उसने बेटी डॉली को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और सितंबर 2023 में बहला–फुसलाकर ले गया था। बेटी को बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। इस मामले में पुष्पेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बेटी ने भी उसके खिलाफ कोर्ट में बयान दिए थे। पुष्पेंद्र इसी मुकदमे में समझौते और बेटी से शादी का दबाव बना रहा था।

बेटी का रिश्ता तुड़वाना चाहता था

भूरी देवी ने बताया कि उन्होंने बेटी डॉली का रिश्ता राजस्थान में तय कर दिया था, लेकिन पुष्पेंद्र ने वहां फोन कर दिया। इससे रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। इसके बाद पति अवधेश यादव, देवर राजेश और देवर के दामाद गौतम द्वारा उसकी हत्या की साजिश रची गई। इसी के तहत पुष्पेंद्र को 25 फरवरी को बेटी द्वारा फोन कर बुलवाया गया। उस दिन घर में राजेश के बेटे की लगन–सगाई थी। पुष्पेंद्र शराब के नशे में आया था। मौका पाकर सभी ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को कार में ही छोड़ दिया। देर रात रिश्तेदारों को विदा करने के बाद शव को लेकर राजस्थान में ठिकाने लगाने के लिए निकले। करीब दो घंटे तक उसे कार में घुमाने के बाद फरह क्षेत्र में ही कार सहित जला दिया। इसके बाद सभी दूसरे वाहन से वापस लौट गए।

23 फरवरी को रची थी साजिश

रिफाइनरी सीओ श्वेता वर्मा ने बताया कि सभी आरोपियों ने 23 फरवरी को ही साजिश रच ली थी कि पुष्पेंद्र को घर बुलाकर उसकी हत्या करेंगे। इसके बाद दुर्घटना का रूप देने के लिए कार सहित जला देंगे। आरोपियों को गिरफ्तारी करने वाली टीम में इंस्पेक्टर कमलेश सिंह, एसआई नितिन तेवतिया, मनोज कुमार, रेखा शर्मा, कांस्टेबल प्रियंका, ताराचंद्र, दीपक कुमार शामिल रहे।

अवधेश, गौतम और राजेश की तलाश जारी

इंस्पेक्टर कमलेश सिंह ने बताया कि पुलिस अब अवधेश, गौतम और राजेश की तलाश में जुटी है। तीनों फरार हैं। इनके रिश्तेदारों के घर, अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द इन आरोपियों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।

मौनी ने कहा
– महादेव और नागिन जैसे बड़े शोज किए

मुम्बई। मौनी राय काफी हद तक इस बात पर सहमत हैं कि फिल्मों में काम करने के बाद टीवी एक्टर्स को ज्यादा सम्मान मिलता है। उन्होंने कहा, 'मैंने महादेव और नागिन जैसे बड़े शोज में काम किया था। हालांकि मुझे ऐसा फील हुआ कि ब्रह्मास्त्र में काम करने के बाद मुझे ज्यादा इज्जत मिलने लगी। यह देख कर थोड़ा बुरा भी लगता है। टीवी इंडस्ट्री मेरे लिए एक घर की तरह है। टीवी ने ही मुझे सब कुछ दिया है। अभी दो–तीन साल पहले तक मुझे कास्टिंग डायरेक्टर सिर्फ यह कहकर रिजेक्ट कर देते थे कि आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम किया है, आप फिल्मों के लिए सूटेबल नहीं हैं।

मुझे लगता है कि टीवी में काम करने से फिल्मों में एक्ट करना आसान हो जाता है। सीरियल्स की शूटिंग के दौरान 15–20 सीन एक–एक दिन में करने होते हैं। इससे एक्टर्स काफी हद तक फिल्मों और ओटीटी शोज में काम करने के लिए निपुण हो जाते हैं। मृणाल ठाकुर और राधिका आप्टे को देख लीजिए। हाल के सालों में इन्होंने टीवी से आकर अपने लिए यहां अलग मुकाम बना लिया है।' श्रेया सरन ने कहा कि एक्ट्रेसेस से पूछा जाता है कि वो बच्चों को पालने के साथ ही फिल्में में काम करना कैसे मैनेज कर पाती हैं। यह बहुत अजीब बात लगती है। श्रेया ने कहा– पहले समय में शर्मिला टैगोर जैसी बड़ी एक्ट्रेस फिल्मों में काम करने के साथ ही बच्चों को भी पाल लेती थीं। उस वक्त ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते थे। क्या किसी मेल एक्टर से यह सवाल पूछा जाता है कि वो फादरहुड के साथ ही काम भी कैसे कर लेते हैं।

हिलवले बाडू' गाने में खेसारी–नीलम की जोड़ी ने मचाई धूम

भोजपुरी गाने आजकल रोजाना सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. कुछ घंटे पहली ही खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज का 'हिलवले बाडू' गाना रिलीज हुआ है. इस गाने को लोगों का कमाल का रिस्पांस मिल रहा है।

: नए भोजपुरी गानों का रिलीज के साथ ही छा जाना साफ बताता है कि समय के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए लोगों की दीवानगी कितनी बड़ी है. खासतौर पर कुछ सिंगर के गाने तो जरूर वायरल होते हैं. इस लिस्ट में खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज का नाम भी शामिल है. कुछ घंटे पहले ही दोनों कलाकारों का एक नया गाना रिलीज हुआ है. इस गाने का नाम है 'हिलवले बाडू.' आइए जानते हैं इस गाने से जुड़ी सारी डिटेल्स.

इंटरनेट पर छाया 'हिलवले बाडू' गाना

खेसारी लाल यादव का नया गाना 'हिलवले बाडू' 'मानस रिकॉर्ड्स भोजपुरी' चैनल पर रिलीज हुआ है. उनके साथ शिल्पी राज ने भी गाने को आवाज दी है. वहीं, वीडियो को शानदार बनाती दिख रही हैं नीलम गिरी. उनका एक–एक मूव कमाल का दिखाई दे रहा है. गाने को लिखा है प्रभु विष्णुपुरी ने और डॉयरेक्ट किया है पवन पाल ने. पिछले कुछ घंटों से यह गाना इंटरनेट पर धूम मचा रहा है.

कमाल की दिखी केमिस्ट्री

'हिलवले बाडू' गाने के लिरिक्स के साथ–साथ मय्यिूक वीडियो को भी कमाल का रिस्पांस मिल रहा है. खेसारी और नीलम की जोड़ी बहुत अच्छी लग ही है. गाने के वीडियो में अलग–अलग शूटिंग लोकेशन दिखाई दे रही है. वहीं, नीलम काली रंग की साड़ी और ब्लाउज में सिर पर टोकरी रख फल बेचती दिखाई दे रही हैं. लोगों को इस गाने में दोनों सितारों की केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रही है.

वायरल हो गया है गाना

हिलवले बाडू गाने को रिलीज के साथ ही बहुत प्यार मिल रहा है. 13 घंटे के अंदर इस गाने पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गए हैं. साथ ही कमेंट सेक्शन में भी पूरे गाने की जमकर वाहवाही हो रही है।

अपने एथनिक वियर में डालें ग्लैमर का तड़का: जाह्नवी कपूर के इन 5 ब्लाउज डिजाइनों से लें आइडिया

महिमा मकवाना ने कहा, 'मुझे लगता है कि लोगों को अपने अंदर संवेदना पैदा करनी चाहिए। अपने अंदर दयाभाव लाना चाहिए। छोटे–बड़े सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए।

इमरान हाशमी ने कहा, 'मैं चाहूंगा कि कुछ लोग अनुशासित हो जाएं। सेट पर समय से पहुंचने की कोशिश करें। सबके समय का ध्यान रखें।'

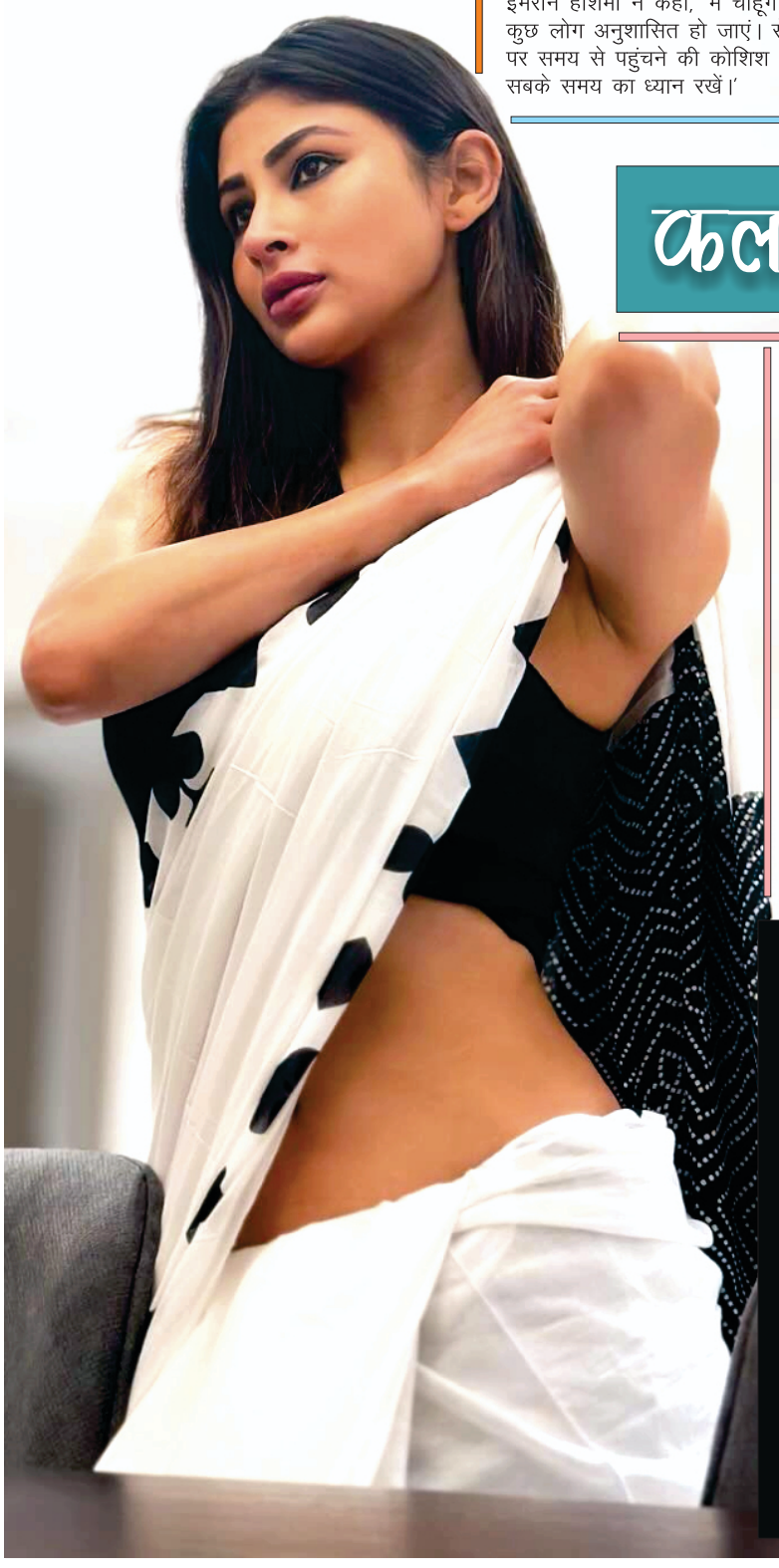

कलाकार बड़ा या छोटा नहीं होता

सबको एक सम्मान मिलना चाहिए

अंत में हमने पूरी स्टारकास्ट से सवाल किया कि अगर उन्हें इंडस्ट्री में कुछ बदलाव करने हों, तो वो क्या होगा? जवाब में राजीव खंडेलवाल ने कहा– कलाकार चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको एक तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हम देखते हैं कि कोई स्टार बड़ा है तो उसके लिए अलग से अरेंजमेंट किए जाते हैं। छोटे कलाकारों को साइड कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी लोग अपना काम ही करने आते हैं। फिल्म के सेट पर मौजूद हर शख्स अपने–अपने एरिया में बेस्ट है, इसलिए सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए।

श्रेया सरन ने कहा– मुझे लगता है कि फिल्मों के लिए स्क्रीन टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौके मिलने चाहिए। इंडस्ट्री में आना हर किसी का सपना होता है। मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लुक टेस्ट में भाग लें ताकि उन्हें ज्यादा मौके मिलें।

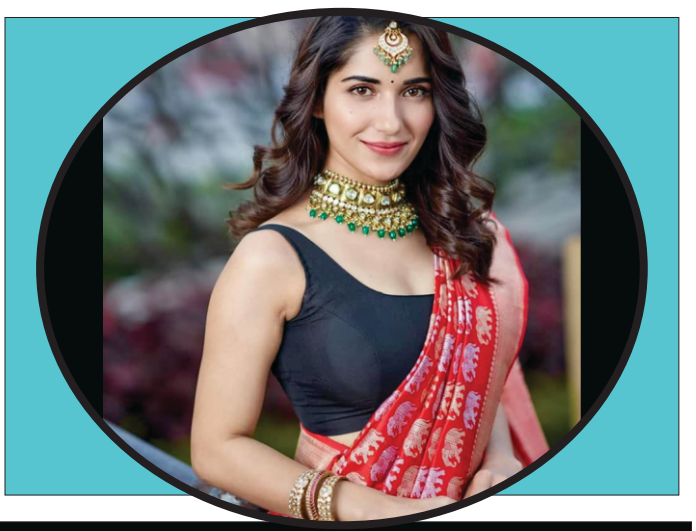

'कुमकुम भाग्य' फेम अभिषेक मलिक ने की तलाक की पुष्टि

शादी के दो साल बाद सुहानी चौधरी से लेंगे तलाक, बोले– रिश्ते में कम्पैटिबिलिटी की कमी थी।

'कुमकुम भाग्य' फेम एक्टर अभिषेक मलिक अपनी पत्नी सुहानी चौधरी से तलाक ले रहे हैं। अभिषेक ने दो साल पहले ही सुहानी के साथ शादी की थी। एक इंटरव्यू के दौरान अभिषेक ने अपने तलाक के खबरों की पुष्टि की। एक्टर ने कहा– हां, ये सच है कि सुहानी और मैं अलग हो रहे हैं। हम दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इसका कारण बताते हुए अभिषेक ने कहा– हमने अपनी शादी में कम्पैटिबिलिटी और समझ जैसी कुछ चीजों की कमी का सामना किया।

अभिषेक ने कहा– तलाक के बाद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे ही पेश आएंगे। उनके बीच कोई हार्ड फीलिंग्स या मनमुटाव जैसी चीजें नहीं आएंगी। बता दें, कपल ने 9 महीने तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी की थी।

हमें एक दूसरे से कोईशिकायत नही है– सुहानी चौधरी

सुहानी चौधरी ने अपने तलाक को लेकर कहा– हमारे बीच कुछ समस्याएं थीं। इस बात का एहसास हम दोनों को तब हुआ, जब हमने साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने कहा– हमें इस बात को लेकर किसी तरह का पछतावा नहीं है ना ही एक दूसरे से किसी तरह कि शिकायत है। हम दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके लिए हमारा अलग होना ही बेहतर होगा। सुहानी ने कहा कि वो अभिषेक के ब्राइट फ्यूचर की कामना करती हैं।

अभिषेक मलिक के सीरियल्स

अभिषेक ने 2012 में 'छल – शह और मात' से टीवी में डेब्यू किया था। इसके अलावा 'दिल की नजर से खूबसूरत', पुनर्विवाह – एक नई उम्मीद, स्प्लिट्सविला का सातवां सीजन, प्यार तूने क्या किया, कैसी ये यारियां, भाग्यलक्ष्मी, एक विवाह ऐसा भी, ये है मोहब्बतें, कहां हम कहां तुम, पिंजरा खूबसूरती का और मुस्कुराने की वजह तुम हो जैसे टीवी शोज में भी नजर आए हैं।

नहीं थम रहा ईशान-श्रेयस को अनुबंध से निकालने का विवाद

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा था कि दोनों क्रिकेटरों को लेकर वार्षिक अनुबंध के लिए विचार नहल किया गया था। इस पर साहा ने कहा कि यह बीसीसीआई का फैसला है और संबंधित खिलाड़ियों का निजी फैसला है।

स्पोर्ट्स डेस्क। भारत के अनुभवी विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा ने गुरुवार को कहा कि अगर कोई क्रिकेटर घरेलू क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है तो कुछ भी 'जबरदस्ती' नहीं किया जा सकता है।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि घरेलू क्रिकेट एक अच्छे खिलाड़ी बनने का आधार है और हर किसी को सफल होने के लिए इसे पर्याप्त महत्व देना चाहिए। साहा की यह प्रतिक्रिया ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को 2023-24 सत्र के लिए बीसीसीआई की वार्षिक केंद्रीय अनुबंध सूची से बाहर किए जाने के बाद आई।

ऋद्धिमान साहा ने क्या कहा?

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा था कि दोनों क्रिकेटरों को लेकर वार्षिक अनुबंध के लिए विचार नहीं किया गया था। इस पर साहा ने कहा, 'यह बीसीसीआई का फैसला है और संबंधित खिलाड़ियों का निजी फैसला है। जबरदस्ती आप कुछ नहीं कर सकते या किसी को खेलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।'

ये दोनों कुछ समय पहले तक भारतीय टीम का हिस्सा थे।

दोनों पिछले साल वनडे विश्व कप भी खेलते दिखे थे। किशन पिछली बार दिसंबर में भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान टेस्ट टीम का हिस्सा थे, जबकि अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज के पहले दो टेस्ट खेले।

घरेलू क्रिकेट को लेकर साहा का बयान

साहा ने कहा कि एक क्रिकेटर को एक मिसाल पेश करते हुए हर मैच को समान महत्व देना चाहिए। उन्होंने कहा, 'जब भी मैं फिट होता हूं तो हर तरह के मैच खेलता हूं, यहां तक कि मैं क्लब मैच, ऑफिस मैच भी खेलता हूं। मैं हमेशा घरेलू मैच को भी एक बड़े मैच की तरह लेता हूं। मेरे लिए सभी मुकाबले बराबर हैं। अगर हर खिलाड़ी इस तरह से सोचता है, तो वे केवल अपने करियर में निखार लाता है और यह भारतीय क्रिकेट के लिए भी बेहतर होगा।'

'घरेलू क्रिकेट की अहमियत हमेशा रहेगी'

उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि घरेलू क्रिकेट की अहमियत हमेशा रही है क्योंकि अगर मैं सरफराज खान की बात करूं तो उन्होंने पिछले चार-पांच साल में काफी रन बनाए हैं। निश्चित रूप से उन्होंने प्रदर्शन किया है।'

साहा ने युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की बल्लेबाजी को शानदार करार दिया। जुरेल ने तीसरे टेस्ट में टेस्ट डेब्यू पर 46 रन बनाए और इसके बाद रांची में चौथे टेस्ट में 90 और 39 नाबाद के स्कोर के साथ प्लेयर ऑफ द मैच बने।

साहा ने की जुरेल की तारीफ

साहा ने कहा, 'मैंने उन्हें (जुरेल) घरेलू क्रिकेट में कभी नहीं देखा और न ही टेस्ट मैचों में मैंने उन्हें खेलते देखा है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी शानदार है। उन्होंने टीम के लिए आखिरी टेस्ट जीता।'

साहा को यह भी लगता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि इसकी बेंच स्ट्रेंथ एक बार फिर घरेलू सर्किट के महत्व को दिखाती है।

उन्होंने कहा, 'यह देखना हमेशा अच्छा होता है कि जब भी किसी को मौका मिलता है तो आपकी रिजर्व बेंच तैयार रहती है।

धर्मशाला में अश्विन रचेंगे इतिहास

खेलेंगे 100वां टेस्ट मैच, सचिन-विराट के क्लब में होंगे शामिल

स्पोर्ट्स डेस्क। धर्मशाला टेस्ट में अश्विन अपने करियर का 100वां मुकाबला खेलते नजर आएंगे। ऐसा करने वाले वह 14वें भारतीय खिलाड़ी होंगे। इसी के साथ दिग्गज ऑफ स्पिनर सचिन तेंदुलकर विराट कोहली जैसे क्रिकेटर्स के क्लब में शामिल हो जाएंगे।

भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज के आखिरी मुकाबले में रविचंद्रन अश्विन इतिहास रचने के लिए तैयार हैं।

100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी

प्लेयर	मैच	प्लेयर	मैच
सचिन तेंदुलकर	200	सौरव गांगुली	113
राहुल द्रविड़	163	विराट कोहली	113
वीवीएस लक्ष्मण	134	इशांत शर्मा	105
अनिल कुंबले	132	हरभजन सिंह	103
कपिल देव	131	चेतेश्वर पुजारा	103
सुनील गावस्कर	125	वीरेंद्र सहवाग	103
दिलीप वेंगसरकर	116	रविचंद्रन अश्विन	99*

सात मार्च को धर्मशाला में दिग्गज स्पिनर अपने करियर का 100वां टेस्ट मुकाबला खेलने के लिए उतरेंगे। इसी के साथ वह सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के क्लब में शामिल हो जाएंगे।

भारत के लिए 99 टेस्ट मैचों में 507 विकेट हासिल कर चुके अश्विन 14वें भारतीय खिलाड़ी होंगे जो 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे। 'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट मुकाबले खेले हैं। उन्होंने 200 मैचों में 15921 रन बनाए।

14वें भारतीय खिलाड़ी बनेंगे अश्विन

इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट में अश्विन ने नया कीर्तिमान स्थापित किया था। अनिल कुंबले के बाद वह भारत के लिए 500 टेस्ट विकेट चटकाने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए। अब वह अपने करियर का 100वां मुकाबला खेलकर नया रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। अश्विन से पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, कपिल देव, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली, इशांत शर्मा, हरभजन सिंह, चेतेश्वर पुजारा और वीरेंद्र सहवाग भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं।

भारतीय जमीन पर चटकाए सर्वाधिक विकेट

रांची टेस्ट में अश्विन भारतीय जमीन पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। अश्विन इस मामले में पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया। कुंबले ने भारतीय मैदानों पर कुल 63 मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 350 विकेट झटके। उन्होंने अपने करियर में कुल 132 टेस्ट में 619 विकेट लिए। अश्विन ने घरेलू मैदान पर अपने 59वें मैच में उन्हें पीछे छोड़ दिया। वह इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में 100 विकेट लेने वाले इकलौते भारतीय हैं। यह उपलब्धि भी उन्होंने रांची टेस्ट में ही हासिल की है।

दिल्ली के आगे नहीं चला आरसीबी का जोर

मंधाना की दमदार पारी के बावजूद मिली करारी शिकस्त

स्पोर्ट्स डेस्क। महिला प्रीमियर लीग के सातवें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 25 रन से हरा दिया। इस टूर्नामेंट में ये आरसीबी की पहली शिकस्त है। वहीं, दिल्ली की दूसरी जीत है। महिला प्रीमियर लीग के सातवें मैच में जीत की हैट्रिक का सपना लेकर उतरी आरसीबी के हाथ निराशा लगी। कप्तान स्मृति मंधाना की अर्धशतकीय पारी के बावजूद टीम को 25 रन से करारी शिकस्त मिली। दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 194 रन बनाए। इसके जवाब में आरसीबी 20 ओवर में नौ विकेट खोकर सिर्फ 169 रन बना सकी। इस टूर्नामेंट में ये आरसीबी की पहली हार है। इससे पहले टीम ने यूपी और गुजरात के खिलाफ जीत दर्ज की थी।

मंधाना की दमदार पारी

195 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत दमदार हुई थी। कप्तान स्मृति मंधाना और सोफी डिवाइन ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। पहले विकेट के लिए दोनों के बीच 77 रन की साझेदारी हुई। डिवाइन 17 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हुईं। वहीं, भारतीय धाकड़ बल्लेबाज मंधाना 43 गेंद में 74 रन बनाकर पेविलियन लौटीं। इस दौरान उन्होंने 172.09 के स्ट्राइक रेट से 10 चौके और तीन छक्के लगाए। उन्हें मारिजन कैप ने आउट किया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरीं ऋचा घोष 19 रन बनाकर आउट हुईं। मारिजन कैप ने जोनासन के हाथों कैच आउट कराया। आरसीबी को चौथा झटका जॉर्जिया के रुप में लगा। उन्हें शिखा पांडे ने आउट किया। जॉर्जिया सिर्फ छह रन बना सकीं। इस मुकाबले में सब्बिनेनी मेघना 36 रन बना सकीं। चार बल्लेबाजों के अलावा आरसीबी का कोई भी बल्लेबाज 10 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाया। इस मैच में दिल्ली के लिए जेस जोनासन ने तीन विकेट लिए। वहीं, मारिजन कैप और अरुंद्धित रेड्डी ने दो-दो सफलता हासिल कीं। शिखा पांडे ने एक विकेट चटकाया।

शेफाली और कैप्सी के बीच ही 82 रन की साझेदारी

आरसीबी के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 194 रन बनाए। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण में उनका सर्वोच्च स्कोर है। इस मुकाबले में सलामी बल्लेबाजी करते हुए मेग लैनिंग और शेफाली वर्मा ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी। हालांकि, दोनों के बीच हुई 28 रन की साझेदारी पांचवें ओवर की पांचवीं गेंद पर समाप्त हो गई।

सोफी डिवाइन ने कप्तान को आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 17 गेंदों में 11 रन बनाए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरीं एलिस कैप्सी ने शेफाली वर्मा के साथ मोर्चा संभाला। दोनों के बीच 82 रन की विशाल साझेदारी हुई। श्रेयंका पाटिल ने भारतीय महिला बल्लेबाज को12वें ओवर कीआखिरी गेंद पर आउट कर दिया। 20 वर्षीय बल्लेबाज ने आरसीबी के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करते हुए शानदार पचासा ठोका। इस टूर्नामेंट में ये उनका दूसरा अर्धशतक है। तीन चौके और चार छक्के की मदद से वह 31 गेंदों में 50 रन बनाने में कामयाब हुईं।

वहीं, एलिस कैप्सी ने भी 46 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि, वह इसे अर्धशतक में तब्दील करने से पहले आउट हो गईं। आरसीबी के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स को पांचवां झटका मारिजैन कैप के रुप में लगा जो तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करती नजर आ रही थीं। 15 गेंदों में 32 रन बनाकर वह पवेलियन लौट गईं। उन्हें सोफी डिवाइन ने 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिमरन बहादुर के हाथों कैच आउट कराया। इसके अलावा जेन जोनासन ने 16 गेंदो में 36 रन की नाबाद पारी खेली। आरसीबी के लिए सोफी डिवाइन और नेदिन डी क्लर्क ने दो विकेट चटकाए। वहीं, श्रेयंका पाटिल को एक सफलता मिली।

दी नेक्स्ट पोस्ट

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक बृजेन्द्र कुमार द्वारा फाइन ऑफसेट प्रिन्टर्स मदरसा हुसैनिया बिल्डिंग बक्सीपुर गोरखपुर से मुद्रित एवं 665 बी गंगा टोला, निकट जानकी बिल्डिंग मैटेरियल बसारतपुर पश्चिमी, गोरखपुर से प्रकाशित। पिनः- 273003

Tital code: UPHIN51019

बृजेन्द्र कुमार
मो0. नं0. 7307180148,9170772370
Email- thenextpost01@gmail.com

नोटः- समाचार पत्र से सम्बन्धित सभी वाद-विवाद गोरखपुर जिला न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होगे।

डब्ल्यूएफआई के ट्रायल का पहलवानों ने किया बहिष्कार, पूनिया बोले- 'जब तक सरकार फैसला नहीं करती हम..

स्पोर्ट्स डेस्क। आंदोलनरत पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती संघ द्वारा आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय ट्रायल में भाग लेने से इनकार कर दिया है। भारतीय कुश्ती संघ द्वारा पेरिस ओलिंपिक और दो एशियन ट्रायल की तारीखों के एलान के बाद आंदोलनरत पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने इसके बहिष्कार की घोषणा कर दी। पहलवानों की मांग है जब तक सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती और उचित समाधान नहीं करती तब तक प्रदर्शनकारी पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा घोषित राष्ट्रीय ट्रायल में हिस्सा नहीं लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने बुधवार को अदालत का रुख किया और संयुक्त याचिका दायर की। इसमें 10-11 मार्च को होने जा रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। हालांकि बजरंग की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया हैं। पिछले दो महीने से रुस में प्रशिक्षण ले रहे बजरंग पूनिया ने साफ किया कि वह ट्रायल का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा उन्होंने सरकार की चुप्पी पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, "अगर मैं ट्रायल में भाग नहीं लेता तो मैं अपने प्रशिक्षण पर 30 लाख रुपये खर्च नहीं करता, लेकिन निलंबित डब्ल्यूएफआई ट्रायल कैसे आयोजित कर रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार की मजबूरी क्या है ।